E-mail: newsroutine6@gmail.com

न्यूज रूटीन

बढ़ते हुए कदम

वर्ष- 04 अंक -11 जनवरी 2026 मूल्य - 35 रु.

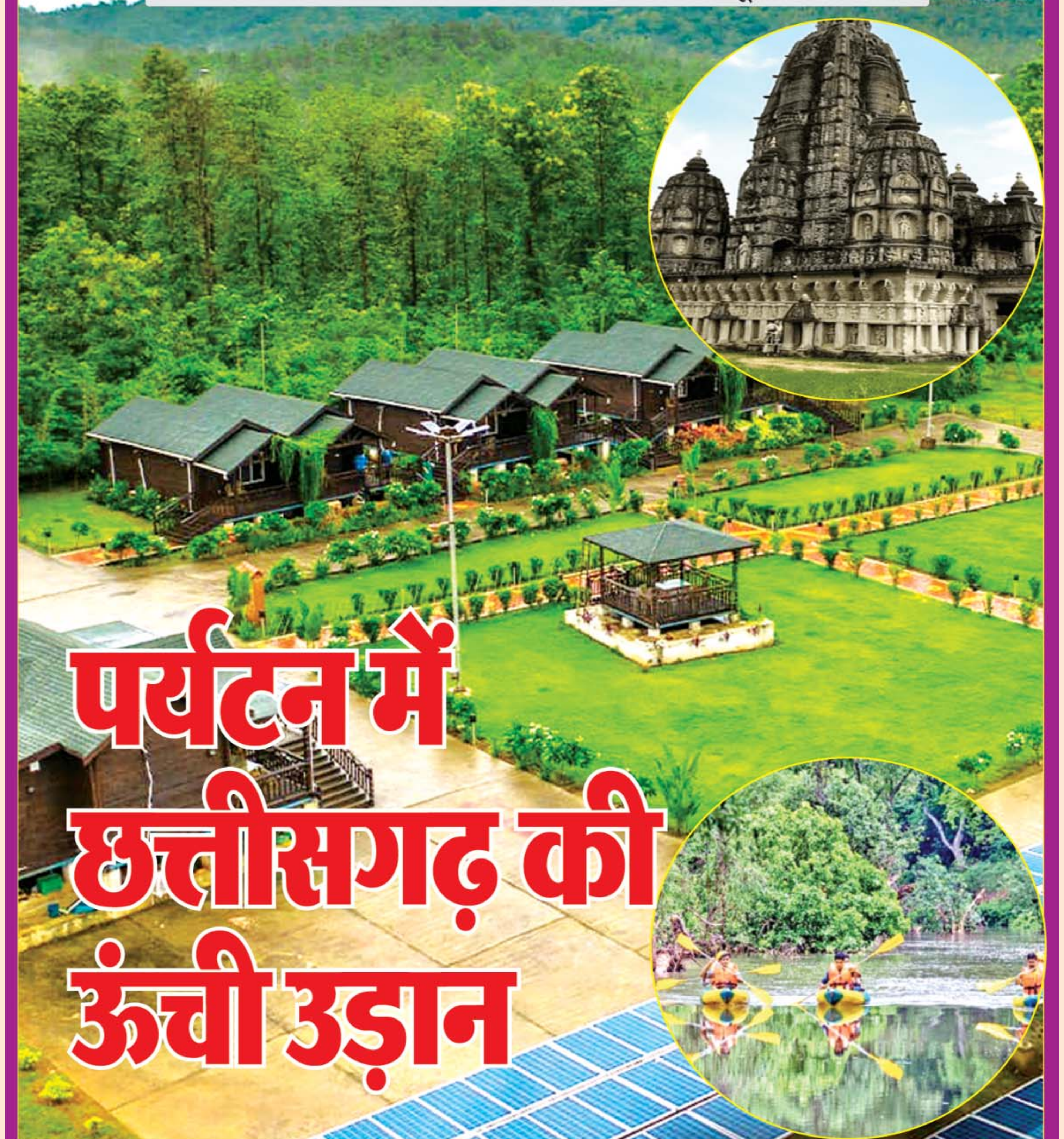

Follow Us :- @newsroutine @newsroutine @newsroutine @newsroutine

लोकतंत्र की पाठशाला बना नेशनल रोवर - रेंजर जंबूरी

युवा संसद में डॉ. रमन सिंह बने अध्यक्ष और बच्चे बने सांसद, लोकहित के मुद्दों पर हुई चर्चा

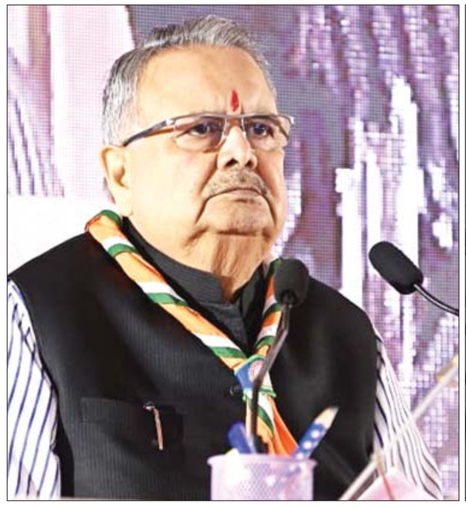

नेशनल रोवर - रेंजर जंबूरी का आयोजन पूरे उत्साह, अनुशासन और जीवंत सहभागिता के साथ बालोद जिले के ग्राम दुधली में सम्पन्न किया रहा है। आयोजन के तीसरे दिन जंबूरी परिसर लोकतांत्रिक चेतना का केंद्र बन गया, जब रोवरङ्करेंजरों एवं उपस्थित नागरिकों को लोकसभा की वास्तविक कार्यवाही का प्रत्यक्ष और व्यावहारिक अनुभव कराया गया। यूथ पार्लियामेंट के मंच पर रोवरङ्करेंजरों ने सांसदों की भूमिका निभाई वहीं विधानसभा के अध्यक्ष संसद के अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन किया। युवाओं ने जिस आत्मविश्वास, विषयगत समझ और मर्यादित संवाद शैली का प्रदर्शन किया, वह दर्शनीय था। यह मंच भावी जनप्रतिनिधियों को गढ़ने का सशक्त माध्यम गया था।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने की आयोजित युवा संसद की सराहना करते हुए कहा कि यूथ पार्लियामेंट के दौरान रोवरङ्करेंजरों जिस प्रकार आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ अपनी भूमिका को निभाया है, उससे देश के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना साकार नजर आती है। आज के युवा कल के हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं। इनके कंधों पर हमारी विरासतों को आगे ले जाने का जिम्मा है, जिसे वे बखूबी निभाएंगे इसका हम सभी को भरोसा है। उन्होंने सभी की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और जिम्मेदार नागरिकता की मजबूत नींव पड़ती है।

इस अवसर पर स्कूली शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने भी युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज के रोवर - रेंजर देश का आने वाला भविष्य है। भारतीय स्काउट गाइड के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉ. के. के. खंडेलवाल, राज्य मुख्य आयुक्त श्री इंद्रजीत सिंह खालसा, जिला मुख्य आयुक्त श्री राकेश यादव, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, रोवरङ्करेंजर, स्काउटङ्कगाइड्स एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे।

जंबूरी का तृतीय दिवस प्रतिभागियों के लिए विविध और प्रेरक गतिविधियों का आयोजन किया गया। जागरण और शारीरिक जांच के साथ फ्लैग सेरेमनी के साथ अनुशासन और एकता का संदेश दिया जाएगा। डॉग शो में कुत्तों की बेहतरीन कलात्मक प्रदर्शन के साथ मार्च पास्ट प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी प्रतियोगिताओं में भी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया।

जम्बूरी में आदिवासी संस्कृति परंपरा के साथ आधुनिकता की अनूठी प्रस्तुति दी गयी। आदिवासी वेशभूषा में पारंपरिक व्यंजनों के निर्माण के साथ लोकवाद्यों की भी प्रस्तुति की गई। आदिवासी नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच पारंपरिक भोजन के साथ ही हॉर्स राइडिंग, बाइक रेस और वाटर एक्टिविटी जैसी साहसिक गतिविधियां का भी प्रदर्शन किया गया।

युवाओं को आपदा प्रबंधन और ग्लोबल डेवलपमेंट विलेज से जुड़ी प्रतियोगिताओं के साथ वृक्षारोपण भी किया गया। कंटीजेंट लीडर मीटिंग, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, एच डब्लू बी रीयूनियन, नाइट हाईक तथा पायोनियरिंग प्रोजेक्ट प्रतियोगिताओं के भी आयोजित की जाएगी। एरिना में आयोजित इंटरनेशनल नाइट कार्यक्रम में विभिन्न संस्कृतियों की रंगारंग प्रस्तुतियां जंबूरी को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बना कोपरा जलाशय

बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय अब छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बन गया है। इसकी घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में प्रसन्नता का माहौल है। यह दर्जा उन आर्द्रभूमियों को दिया जाता है जो जैवविविधता, जल संरक्षण और पर्यावरणीय महत्व के लिए वैश्विक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि कोपरा जलाशय की यह सफलता छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि जलाशय की विशिष्ट पारिस्थितिकी, स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की विविधता तथा जल परितंत्र की समृद्धि ने इसे रामसर मान्यता के योग्य बनाया है। वन मंत्री श्री कश्यप ने राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, पर्यावरणविदों, वन विभाग के अधिकारियों, शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदायों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि सभी की संयुक्त मेहनत और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता से यह उपलब्धि संभव हो सकी है।

मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 20 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिलाने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि कोपरा जलाशय के रामसर साइट घोषित होने से प्रदेश में वेटलैंड संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और इको-टूरिज्म के नए अवसर भी विकसित होंगे। इससे स्थानीय समुदायों को रोजगार मिलेगा और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा और संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि वेटलैंड्स का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत प्राकृतिक विरासत छोड़ने का संकल्प भी।

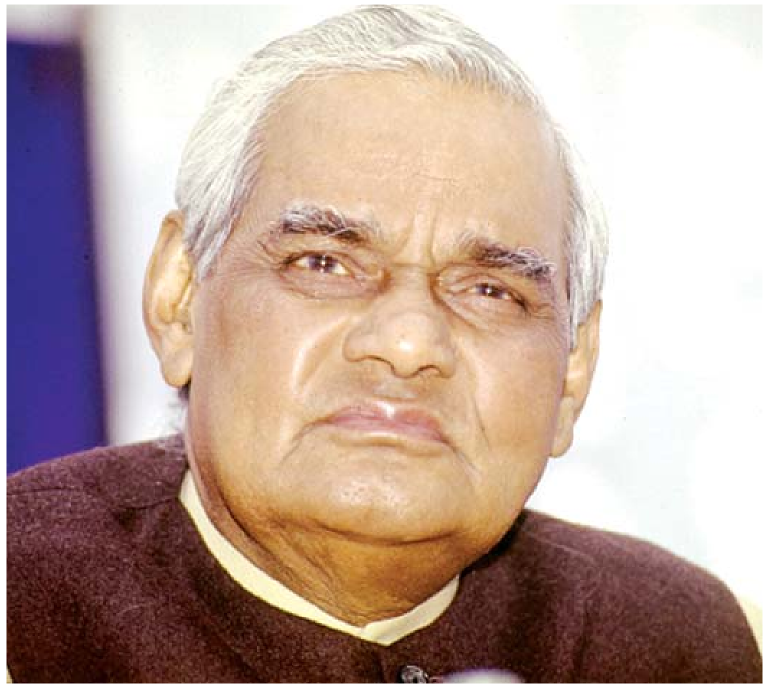

अटल जी जन-जन से प्रेम करने वाले जननायक हैं। वे एक अप्रतिम वक्ता, संवेदनशील कवि और विचारवान लेखक के साथ भारत के महान नेता है। उनका समग्र व्यक्ति त्व अभ्यर्थना और अवमानना के मोह पाश से मुक्त है।

भारतीय राजनीति के नक्षत्र अटल जी

चन्द्रशेखर साहू
पूर्व मंत्री, छ.ग. शासन

'हम टूट सकते हैं, झुक नहीं सकते' अटल बिहारी वाजपेयी जी पर यह उक्ति सटीक बैठती है जब आपातकाल (इमरजेन्सी) के दौरान उन्होंने अपने गम्भीर पीट दर्द के चलते चिकित्सीकीय लाभ और जेल से रिहा होने के लिए इंदिरा जी के संदेश को स्वीकार नहीं किया था। आपातकाल के अनेक प्रसंग त्रासदायी है उसमें भी अटल जी ने अपनी रचनाधर्मी सोच को लोकत्रांत्रिक कलेवर देकर सबको झझकोरा और आशावादी अंतर्धारा को प्रवाहित कर इस उक्ति को राष्ट्रीय धरातल पर चरितार्थ किया। तभी परिवर्तन दुनिया के सामने एक नई राजनीतिक संस्कृतिक का उदय जनता पार्टी के रूप में सन् 1977 में हुआ।

मुख्य तौर पर अटल जी के दीर्घ संसदीय जीवन आज भी लोकतंत्र की आईना के रूप में है, जिसे वर्तमान से लेकर अतीत के राजनीतिक प्रतिबिम्बों को निहारने के साथ ही परखा जा सकता है। अनेक विषयों पर उनका भाषण कालजयी तो है ही सामाजिक जीवन में उम्मीदों का अध्याय भी है। बारहवीं लोकसभा में एक सदस्य के तौर पर यद्यपि मुझे 13 महीने ही कार्य करने का अवसर मिला, परंतु इतने ही कालखण्ड में उनकी संसदीय विधाओं के प्रयोग को मैंने नये आकार लेते हुए देखा। संसद में बहस के दौरान मनुष्य की अदम्य लालसा तथा राजनैतिक महत्वाकांक्षा पर उनके व्यंग्य वाक्य आज भी राजनीतिक कोहरे में इन्द्रधनुष के लकीर की तरह है, जहाँ भारतीयता की पहचान अपनी चमक अलग दिखाई देती है। तीन

आज से दशक पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक साक्षात्कार में स्वराज और धर्मनिरपेक्षता पर बेवाक विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि स्वदेशी और विदेशी में फर्क काफी संकरा हो गया है। इण्डिया और भारत में अन्तर को भी पाटना इसी पृष्ठभूमि में आज की जरूरत है। भारतीय बने रहने के प्रति अधिक सचेत हो सकते हैं। उनके धुर विरोधी भी स्वीकारते हैं कि अटल जी इस कालखण्ड के सबसे समावेशी राष्ट्रवादी नेता है, जिन्होंने भारतीय अस्मिता को जाग्रत करने के लिए वैश्विक मंच का उपयोग किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिन्दी में भाषण देने का प्रथम राजनेता होने का गौरव हासिल किया।

आर्थिक सुधारों के लिए भी अटल जी ने जो राजनैतिक दर्शन और अपना आधार बनाया वह था 'सर्वानुमिति का मंत्र' जैसे आज भारत के शीर्ष राजनैतिक नेतृत्व ने भी 'सबका विकास, सबका साथ' को मूलमंत्र की मान्यता दी है।

तेजी से बदलते आर्थिक-सामाजिक ताना-बाना को उन्होंने केवल आर्थिक सुधार का हिस्सा नहीं माना बल्कि उसके लिए सांस्कृतिक मुड़भेड़ (कल्चरल इनकाउण्टर) को कारण बताया है और नब्बे की दशक से शुरू हुये आर्थिक सुधारों में अवरोधों को दूर करने में नया नजरिया को स्वीकार्य बनाया। इसी दो दशक में आर्थिक मंदी का असर वैश्विक पटल पर दृष्टिगोचर हो रहा था तब भी भारत के आम आदमी तथा भारत भूमि के असली ताकत का अहसास उन्होंने विश्व के महाशक्तियों को समय रहते कराया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था पोखरण का परमाणु विस्फोट भारत के इस कदम से अमेरिका सहित कई विकसित राष्ट्र अचंभित एवं किंकर्तव्यविमूढ़ थे। आज भी अमेरिका के नीति-नियंता वर्ग को इस बात का मलाल है कि उनके पास इसकी जानकारी पहले कैसे नहीं आ पाई। परमाणु विष्फोट के बाद की परिस्थितियों में सबने देखा कि भारत के परमाणु शक्ति सम्पन्न होते ही अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध का ऐलान कर दिया। तत्काल अटल जी ने संसद में और देशवासियों का अपने सम्बोधन में कहा था कि भारतीय लोकतंत्र के असली ताकत यहाँ के किसान, मजदूर, युवा, महिला हैं। इसलिए आर्थिक प्रतिबंध (इकॉनामिक संक्शन) का असर भारत के अर्थव्यस्था में नहीं पड़ने वाला है, और न ही हम किसी के आगे झुकने वाले हैं। उनकी पक्ति अब फिर से प्रासंगिक हो गई है कि दाँव पर सब कुछ लगा है रूक नहीं सकते

अटल जी जन-जन से प्रेम करने वाले जननायक हैं। वे एक अप्रतिम वक्ता, संवेदनशील कवि और विचारवान लेखक के साथ भारत के महान नेता है। उनका समग्र व्यक्तित्व अभ्यर्थना और अवमानना के मोह पाश से मुक्त है। वे काव्य व्यक्तित्व के छंद बन गये हैं जिसमें उत्साह का प्रवाह निरंतर होता रहता है। हम यह कह सकते हैं कि अपनी स्वच्छ एवं निष्ठा प्रधान विचारधारा के कारण वे उपमेय से उपमान बन गये हैं। आकाश के सप्तर्षि मण्डल को हम आप देखते ही होंगे वह एक नक्षत्र की परिकमा किया करता है। अटल जी मेरी दृष्टि में भारतीय राजनैतिक गगन के नक्षत्र बन गये हैं 'गुंज उठी गीता की वाणी, मंगलमय जन-जन कल्याणी। अपढ़ अजान विश्व ने पाई, शीश झुकाकर एक धरोहर ।।'

न्यूज रूटीन

बढ़ते हुए कदम

● वर्ष: 04 ● अंक:11 ● जनवरी 2026

RNI NO. CHHHIN/2022/83778

E-mail: newsroutine6@gmail.com

सारंगढ़-बिलाईगढ़

प्रधान संपादक
गुलाब दास दीवान

सहसंपादक
प्रवीण खरे

कानूनी सलाहकार
जवाहर पड़वार
इंदुभूषण पड़वार

प्रधान कार्यालय

न्यूज रूटीन
बाजार काम्पलेक्स, नगर पंचायत पवनी,
जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़
पिन. नं. 493338
मो.नं. 9294743139

रायपुर कार्यालय
फ्लैट नं. 109, सी ब्लाक, कमल हाईट्स,
सेक्टर-4, कमल विहार, रायपुर (छ.ग.)
पिन नं. 492004
मो. नं. 6261155546

न्यूज रूटीन में प्रकाशित आलेखों से संपादक, प्रकाशक, मुद्रक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। विवादग्रस्त न्यायिक प्रकरणों का कार्यक्षेत्र सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला रहेगा। सभी पद पूर्णतः मानसेवी व अवैतनिक। समाचार स्त्रोत हमारे सभी संवाददाता/प्रतिनिधि। संदर्भ सामग्रीः इंटरनेट, प्रमुख समाचार पत्र एवं नामचीन पत्रिकाओं से सादर साभार।

संपादक- गुलाब दास दीवान

अंदर के पृष्ठों में

05 146 करोड़ रूपए की लागत से होगा भोरमदेव कॉरिडोर निर्माण

12 संगठन, रणनीति और सत्ता संतुलन का नया अध्याय

- यूनेस्को की दहलीज पर सिरपुर 7
- गिद्ध संरक्षण में छत्तीसगढ़ की नई उड़ान 9
- अस्पताल की दहलीज पर अब परिजनों को मिलेग... 11
- कांगेर घाटी में मिली अनोखी 'ग्रीन गुफा' 16
- इन्दौर की जल-त्रासदी और प्रशासनिक लापरवाही..... 19
- नदी-नाले पार कर बचाया गया भविष्य 22
- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने रचा आवास क्षेत्र में... 23
- जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय मे 24
- पर्यटन को उद्योग बनाना छत्तीसगढ़ का साहसिक दांव 25
- बच्चों की नसों में उतरता नशा और हमारी लापरवाही 29

लोगों की उम्मीदें तत्परता से हो रही पूरी 17

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक- गुलाब दास दीवान, द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. (छ.ग.) भवन, प्रेस काम्पलेक्स रजबंधा मैदान रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.), 493338 से प्रकाशित। RNI NO. CHHHIN/2022/83778 सम्पादक- गुलाब दास दीवान, मो. 9294743139

अंतरिक्ष में भारत का 'बाहुबली'

यह मिशन भविष्य में इंटरनेट जुड़ाव को बदलने वाला भी साबित होगा। इन उपलब्धियों पर अचरज भी होता है। भारत का अंतरिक्ष में अपना स्टेशन भी होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार यह घोषणा की है।

इस बार भारत ने अंतरिक्ष में 'बाहुबली छलांग' लगाई है। भारत ने सबसे अधिक वजन वाला, वाणिज्यिक उपग्रह, भेजने का भी कीर्तिमान स्थापित किया है। जिस अमरीकी 'ब्लूबर्ड ब्लॉक-2' उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने का इतिहास भारत ने रचा है, उससे संचार की दुनिया का चेहरा ही बदल जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर से एलवीएम-3 के रॉकेट के जरिए भारत ने 6100 किग्रा. का उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा तक भेजकर कीर्तिमान का एक और मील पत्थर स्थापित किया है। इससे पहले यह कीर्तिमान 4400 किग्रा. के सीएमएस-03 संचार उपग्रह के नाम था, जो 2 नवंबर को प्रक्षेपित किया गया था। इसरो की वाणिज्यिक शाखा 'न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड' ने अमरीकी कंपनी 'एएसटी स्पेसमोबाइल' के साथ करार किया था। लॉन्चिंग के 15 मिनट बाद ही यह उपग्रह रॉकेट से अलग हो गया और करीब 600 किमी. दूर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित हो गया। प्रक्षेपण और उड़ान में मात्र 90 सेकंड की देरी इसलिए हुई, क्योंकि उपग्रह के उड़ान-पथ पर मलबा होने अथवा अन्य उपग्रहों के साथ टकराव की संभावनाएं थीं। इस 'बाहुबली उपग्रह' से संचार और मोबाइल की दुनिया इस कदर बदल जाएगी कि दुनिया में कहीं भी, पहाड़ों के बीच भी, 4 जी और 5जी सुविधा वाले मोबाइल से वॉयस और वीडियो कॉल, संदेश, स्क्रीमिंग, डाटा सेवाएं सहज और सुलभ हो जाएंगी। अब नेटवर्क की कोई भी चिंता नहीं होगी। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष से सीधे धरती पर कॉल की जा सकेंगी। संदेश भेजना संभव होगा। वीडियो कॉल के जरिए हम सब, एक-दूसरे के, रूबरू होंगे। क्या भारत ने इतनी विराट, अंतरिक्षी सफलता की कल्पना तक की थी? आर्यभट्ट से लेकर ब्लूबर्ड तक भारत ने एक बहुत लंबा और पेचीदा सफरनामा तय किया है। गौरतलब यह है कि पहली बार इसरो ने 52 दिनों की तैयारी में इस उपग्रह को लॉन्च किया है, जो एलएमवी-3 जैसे बाहुबली के लिए बहुत कम समय है।

इस रॉकेट में पहली बार एस 200 बूस्टर को नियंत्रित करने के लिए नए कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। यही सिस्टम 'गगनयान मिशन' में भी इस्तेमाल होना है, लिहाजा एक तरह से उसकी सफल टेस्टिंग हो गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के सफल लक्ष्यों की कहानी भी सामने आई है, क्योंकि 2026 में हर माह एक लॉन्चिंग होगी। उसमें सबसे खास मिशन 'गगनयान' है। कुछ स्टार्टअप के ऑर्बिटल लॉन्च भी होने हैं। 2040 तक चंद्रमा पर मानव को उतारने का लक्ष्य तय किया गया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 8-10 विश्व कीर्तिमान रचने की भी योजना है। आज यह याद करने का भी दिन है कि 2014 में इसरो ने 'मंगलयान' के साथ पहली कोशिश की थी और भारत प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम देश बन गया था। 2017 में पीएसएलवी-सी 37 के साथ भारत ने एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर भी इतिहास रचा था। 2023 सबसे महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ, जब हमारा 'चंद्रयान-3' चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर सका। वहां हमने 'तिरंगा' स्थापित किया। 'ब्लूबर्ड-2' के प्रक्षेपण और पृथ्वी की कक्षा में सफल स्थापना ने भी भारत की इन उपलब्धियों को एक और सेहरा पहनाया है। जो उपग्रह भेजा गया है, वह दुनिया भर में स्मार्टफोन को सीधे हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। उपग्रह में 223 वर्ग मीटर का विशाल, एक खास किस्म का, एंटीना लगा है, जो अब तक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला सबसे बड़ा वाणिज्यिक, संचार उपग्रह बनाता है। 'ब्लूबर्ड' की मदद से स्मार्टफोन वाणिज्यिक और सरकारी दोनों उद्देश्यों के लिए सीधे उपग्रहों से जुड़ सकेंगे। यह मिशन भविष्य में इंटरनेट जुड़ाव को बदलने वाला भी साबित होगा। इन उपलब्धियों पर अचरज भी होता है। भारत का अंतरिक्ष में अपना स्टेशन भी होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार यह घोषणा की है। उस दिन भारत अंतरिक्ष के भी सातवें आसमान पर होगा। बहरहाल इसरो को इस उपलब्धि के लिए बधाई। हालांकि यह कारवां और आगे जाना चाहिए। अभी कई कुछ करना बाकी है।

संपादक

बच्चों की नसों में उतरता नशा और हमारी लापरवाही

अनुज का स्कूल बैग साफ करते वक्त जब उसकी एक किताब के बीच से गुटखे की खाली पन्नी फिसल कर ज़मीन पर गिरी, तो रश्मि का दिल जैसे एक पल को थम सा गया।अनुज अभी सिर्फ़ 11 साल का है। पाँचवीं कक्षा में पढ़ता है। उसके बस्ते में गुटखा? यह सवाल नहीं, एक चेतावनी थी।

रश्मि देर तक उसी पन्नी को देखती रही। दिमाग़ में शोर मच गया। सिर में दर्द होने लगा। अनुज उस समय पार्क में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। मन हुआ—अभी बुलाकर पूछे। लेकिन रुक गई। सोचा, पहले उसके पिता को बताएगी। मगर शाम ढल गई, रात बीत गई और वह कुछ नहीं कह पाई। क्योंकि वह जानती थी—अगर बताया तो समस्या का हल नहीं निकलेगा, बल्कि दोषारोपण शुरू हो जाएगा।

'तुम ठीक से परवरिश नहीं कर पा रही हो। दिन भर घर में करती क्या हो ?,बच्चे पर नज़र क्यों नहीं रखती ?, तुमने इसे सिर पर चढ़ा रखा है।' ऐसी बातें, जो ज़हर से कम नहीं होतीं। जिनमें चिंता नहीं, सिर्फ़ आरोप होता है।

अगले दिन अनुज स्कूल से लौटा, बस्ता पटककर खेलने निकल गया। रश्मि ने इस बार पूरा बस्ता उलट-पुलट कर देख डाला। अंदर की जेब से गुटखे की एक पुड़िया निकली—आधी भरी हुई। अब भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं थी। शाम को जब अनुज लौटा, तो रश्मि का संयम टूट चुका था। पुड़िया सामने रख कर सवाल किए। अनुज का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पहले उसने इनकार किया। लेकिन जब गुस्से में एक थप्पड़ पड़ा, तो रोते हुए सारी कहानी बाहर आ गई।

स्कूल में उसकी दोस्ती आठवीं में पढ़ने वाले दो लड़कों से हो गई थी। वे उसे अपने साथ क्रिकेट खिलाते थे। स्कूल के पीछे मैदान की बाउंड्रीवाल टूटी हुई थी। उसी रास्ते से वे अनुज को बाहर भेजते—सामने की गुमटी से गुटखा लाने। खुद भी खाते, उसे भी चखाते। कभी-कभी अनुज अपनी पॉकेटमनी से भी खरीद लेता।

रश्मि जैसे सुन्न पड़ गई।

कब से?

छह महीने से।

अनुज ने बताया—पहली बार चक्कर आया था, गिर पड़ा था। वही लड़के संभाल कर घर तक छोड़ आए थे।

लेकिन अब,

अब उसे ताक़त महसूस होती है। थकान नहीं लगती। खेल में 'मज़ा' आता है। यही वह क्षण था जब रश्मि को समझ आया—यह सिर्फ़ उसका बच्चा नहीं है। यह एक पूरी पीढ़ी की कहानी है।

यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है। देश के दस बड़े शहरों में किए गए एक सर्वे ने बताया है कि बच्चे औसतन 12.9 साल की उम्र में पहली बार किसी नशीले पदार्थ के संपर्क में आ रहे हैं। कुछ तो 11 साल के भी हैं। 'नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया' में प्रकाशित रिपोर्ट कहती है—हर सात में से एक स्कूल जाने वाला बच्चा कभी न कभी किसी साइकोएक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल कर चुका है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, चंडीगढ़, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, डिब्रूगढ़ और रांची—देश के नामी स्कूलों में यह हाल है। तो ज़रा सोचिए—छोटे शहरों, कस्बों और गलियों में क्या स्थिति होगी? जहाँ स्कूल की दीवार से सटी पान गुमटी खड़ी होती है। नशा यहाँ चोरी-छिपे नहीं बिकता। यह खुलेआम बिकता है। कानून की तख़्तियों के नीचे।

डॉक्टरों ने साफ़ कहा है—जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, नशे की पकड़ गहरी होती जाती है। और इसके साथ बढ़ती है मानसिक परेशानी—व्यवहार की समस्याएँ, अतिसक्रियता, भावनात्मक अस्थिरता। लेकिन सबसे डरावनी सच्चाई यह है— आधे से ज़्यादा बच्चे मानते हैं कि वे नशा करने की बात छुपाएंगे। यानी जो दिख रहा है, वह पूरा सच नहीं है।

यह सिर्फ़ गुमटियों का अपराध नहीं है। यह सिर्फ़ पुलिस की नाकामी नहीं है। यह हमारे घरों की चुप्पी का नतीजा है। आज के माता-पिता कमाने की दौड़ में इतने उलझे हैं कि बच्चों के मन तक पहुँचने का रास्ता खो चुके हैं। घर में बातचीत की जगह स्क्रीन है। संस्कार की जगह कंटेंट। बच्चा किससे दोस्ती कर रहा है? किसके साथ खेल रहा है? कौन उसे प्रभावित कर रहा है? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं हैं। नशे का कारोबार धीरे-धीरे, बिना शोर के, हमारे बच्चों की नसों में उतर रहा है।यह सामाजिक नरसंहार है—जिसमें लाशें नहीं गिरतीं,लेकिन समाज खोखला हो जाता है। और इस सच्चाई से हम बच नहीं सकते कि इस विनाश की पहली ज़िम्मेदारी, हम माता-पिता की है।

जो समय रहते नहीं देखते।
नहीं सुनते।
और जब तक समझते हैं—
तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।

G-RAM-G बिलः MGNREGA का अंत या राज्यों पर वित्तीय बम?

भारत के ग्रामीण भारत की आत्मा—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)—को बदलने के केंद्र के प्रयास ने अब तक के सबसे संवेदनशील राजनीतिक और संघीय मुद्दों में से एक को जन्म दिया है। भारत में ग्रामीण रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में 2005 में शुरू हुआ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) न केवल गरीब ग्रामीणों की जीवनरेखा बन चुका था, बल्कि यह केंद्र–राज्य सहयोग और संघीय ढांचे की मजबूती का प्रतीक भी था। लेकिन 2025 में केंद्र द्वारा पेश किया गया विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल – G-RAM-G इस संतुलन को उलटने की कोशिश करता नजर आता है।

बिल का पहला और सबसे ध्यान खींचने वाला बदलाव है MGNREGA से महात्मा गांधी का नाम हटाकर इसे G-RAM-G कहना। यह सिर्फ़ प्रतीकात्मक परिवर्तन नहीं है, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। नामकरण में हिंदू पहचान जोड़कर केंद्र ने एक ऐसा संकेत भेजा है जो स्पष्ट रूप से भाजपा की राजनीति और राज्य के संघीय संबंधों को प्रभावित करता है।

लेकिन समस्या केवल नाम की नहीं है। G-RAM-G बिल वित्तीय बोझ और राज्य–शक्ति के असंतुलन की तरफ इशारा करता है। MGNREGA में केंद्र 100 प्रतिशत मज़दूरी का भुगतान करता था, जबकि अब प्रस्तावित बिल के तहत अधिकांश राज्यों को केवल 60 प्रतिशत मज़दूरी केंद्र द्वारा मिलेगी। शेष 40 प्रतिशत का बोझ राज्य सरकारों पर डाला जाएगा। केवल पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्य और बिना विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश ही 90 प्रतिशत केंद्र सहायता प्राप्त करेंगे।

केंद्र द्वारा यह बदलाव स्पष्ट रूप से विपक्षी शासित राज्यों के लिए वित्तीय संकट का नया दरवाज़ा खोलता है। उदाहरण के लिए, केरल को MGNREGA के मौजूदा रोजगार स्तर को बनाए रखने के लिए हर साल कम से कम 2,500 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च उठाना होगा। यह स्थिति उन राज्यों के लिए चिंताजनक है, जिनकी खजाने पहले ही खाली हैं और जो केंद्र से समय पर भुगतान और अतिरिक्त फंडिंग की उम्मीद करते रहे हैं।

केंद्र का संघवाद पर हमला

G-RAM-Gबिल राज्यों के अधिकारों पर भी सीधा हमला करता है। पहले राज्यों को अपनी वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर केंद्र से फंड आवंटन की मांग करने का अधिकार था। अब केंद्र 'ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स' के आधार पर सालाना नॉर्मेटिव एलोकेशन तय करेगा। इसका मतलब स्पष्ट है–

- राज्यों की वित्तीय योजना और प्राथमिकताओं पर नियंत्रण केंद्र का होगा।
- यदि राज्य अपने नॉर्मेटिव एलोकेशन से अधिक खर्च करता है, तो अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार को उठाना होगा।
- केंद्र G-RAM-Gके तहत काम के स्थान और अवधि को तय करने का अधिकार भी रखेगा।

विशेष रूप से कृषि चरम मौसम के दौरान काम को सीमित करने का प्रावधान, सीधे तौर पर ग्रामीण मज़दूरों के लिए साल में काम की उपलब्धता घटा देगा। यह वही 'अधिकार–आधारित ढांचा' खत्म करता है, जिसके तहत MGNREGAकाम करता था।

राजनीतिक और वित्तीय चुनौती

कांग्रेस, CPI(M) और तृणमूल जैसी पार्टियाँ पहले ही विरोध कर रही हैं। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलका कहते हैं कि यह बिल पिछले वर्षों में संसदीय समिति द्वारा MGN-REGA सुधार के प्रयासों के खिलाफ है। CPI सांसद वी. शिवदासन इसे 'ग्रामीण आजीविका पर खुला हमला' बताते हैं।

सिर्फ़ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। MGNREGAके तहत 100 दिन प्रति वर्ष रोजगार अब 125 दिन का दिखावटी विस्तार है, लेकिन वित्तीय बोझ बढ़ने के कारण यह बदलाव राज्यों पर दबाव डालकर अमल में मुश्किल हो जाएगा।

संघवाद और फंडिंग असंतुलन के अलावा, यह बिल केंद्र–राज्य संबंधों में नया तनाव पैदा कर रहा है। विपक्षी शासित राज्य, जिनकी प्राथमिकता अपने नागरिकों को समय पर रोजगार देना है, इस स्थिति में वित्तीय और प्रशासनिक रूप से दवाब में हैं।

नज़रिए की बड़ी तस्वीर

G-RAM-G बिल केवल कानून का बदलाव नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश और केंद्र की शक्ति का विस्तार है। अगर यह बिल लागू होता है–

- राज्य केंद्र पर अधिक निर्भर होंगे।
- ग्रामीण गरीबों को वास्तविक लाभ कम मिलेगा।
- संघीय ढांचे में असंतुलन और राज्यों के खिलाफ वित्तीय दंड बढ़ेगा।
- MGNREGA के अधिकार–आधारित मूल सिद्धांतों को खत्म करने का रास्ता खुल जाएगा।

MGNREGA सिर्फ़ एक योजना नहीं, यह गरीब ग्रामीणों का हक़, केंद्र–राज्य सहयोग और लोकतांत्रिक संघवाद का प्रतीक था। G-RAM-Gबिल न केवल इसके वित्तीय मॉडल को कमजोर करता है, बल्कि राज्यों की स्वायत्तता, ग्रामीण रोजगार और भविष्य की आजीविका पर भी खतरा डालता है।

यदि केंद्र और राज्य सहयोग नहीं करते हैं, तो ग्रामीण आजीविका संकट की ओर बढ़ सकती है। यह सिर्फ़ एक बिल नहीं, भारत के

146 करोड़ रूपए की लागत से होगा भोरमदेव कॉरिडोर निर्माण

केन्द्रीय मंत्री शेखावत एवं मुख्यमंत्री साय ने किया भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना का भूमिपूजन

स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत भोरमदेव मंदिर परिसर से मड़वा महल, छेरकी महल, रामचुआ एवं सरोदा जलाशय तक एक सुव्यवस्थित एवं समग्र पर्यटन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा।

केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के विकास का ग्रोथ इंजन छत्तीसगढ़ बनता जा रहा है छत्तीसगढ़ इस संकल्प के साथ में हम सब लोग काम करेंगे ऐसा भरोसा और विश्वास आप सबको दिलाते हुए आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सतत आगे बढ़े और छत्तीसगढ़ का पर्यटन विकसित हो छत्तीसगढ़ की संस्कृति सुरक्षित और संरक्षित हो जिससे छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान बने। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत 146 करोड़ रुपये की लागत से भोरमदेव कॉरिडोर निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन सम्पन्न किया गया। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत भोरमदेव मंदिर परिसर से मड़वा महल, छेरकी महल, रामचुआ एवं सरोदा जलाशय तक एक सुव्यवस्थित एवं समग्र पर्यटन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण होने से जिले के प्रमुख धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थलों को एक सशक्त पर्यटन श्रृंखला में जोड़ते हुए भोरमदेव को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी। उज्जैन और वाराणसी की तर्ज पर भोरमदेव कॉरिडोर का विकास किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, उपमुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने नववर्ष के अवसर पर कबीरधाम जिले को बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा के आग्रह पर भोरमदेव से बोड़ला तक सड़क चैड़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य की भी घोषणा की।

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने भोरमदेव महोत्सव स्थल पर कॉरिडोर के भूमिपूजन के बाद सभा को संबोधित करते हुए कबीरधाम जिले सहित पूरे प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। उन्होंने नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि बीते दो वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को धरातल पर उतारते हुए विकसित छत्तीसगढ़ की

परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी, जिसे समाप्त करने का बीड़ा राज्य सरकार ने उठाया है और आज प्रदेश नक्सलवाद की समाप्ति की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के नागरिकों में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि भारत को कमजोर करने वाली किसी भी ताकत या षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध लिए गए कठोर निर्णयों ने देश की सुरक्षा नीति को नई मजबूती प्रदान की है।

उज्जैन और वाराणसी की तर्ज पर भोरमदेव कॉरिडोर का विकास किया जाएगा

केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि भारत तेजी से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। सड़कों, पुल-पुलियों एवं अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, पेयजल, बिजली, डीबीटी के माध्यम से राशि का अंतरण और रोजगार जैसी सुविधाएं गरीबों के घर-घर तक पहुंच रही हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सकारात्मक बदलाव करते हुए अब 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। साथ ही रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में हर्जाने की गारंटी भी इस योजना में शामिल की गई है। उन्होंने इसे 'मोदी की गारंटी' बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि भोरमदेव मंदिर लगभग एक हजार वर्ष पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है और इस कॉरिडोर निर्माण के माध्यम से आने वाले हजार वर्षों तक इसे संरक्षित रखने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने निर्माण एजेंसियों एवं अधिकारियों से आग्रह किया कि 146 करोड़ रुपये की इस परियोजना में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए, क्योंकि यह कार्य धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि एक हजार साल पुराने बाबा भोरमदेव के मंदिर विकास हेतु आज भूमिपूजन हुआ है जो बहुत ही हर्ष की बात है। सावन के महीने में यहां हजारों की संख्या श्रद्धालु कावड़िये अमरकंटक से माता नर्मदा का जल लेकर बाबा भोरमदेव का जलाभिषेक करते हैं जिनका स्वागत करने के लिए उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के साथ मैं भी आया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शासन ने हर वर्ग के विकास के लिए निरन्तर कार्य किया जा रहा है। कवर्धा के जंगलों में वास करने वाले राष्टपति के दत्तक पुत्र कहलाने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के बैगा जैसे प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों के लिए शासन द्वारा पीएम जनमन योजना प्रारम्भ की गई है, जिससे अब गांव-गांव तक पक्की सड़कें, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे अनेक योजनाओं का लाभ यहां के लोगों को मिल रहा है।

वहीं उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रारम्भ किए गए हैं, जिनमें एंबुलेंस के साथ में डॉक्टर एवं नर्स सहित पूरा तकनीकी स्टाफ भी उपलब्ध रहेगा जो घर घर जाकर लोगों का उपचार करेगा। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वादे किए थे जिन्हें पूरा करने का कार्य शासन द्वारा किया जा रहा है। मोदी की गारंटी को काम पूरा होने की गारंटी बताते हुए उन्होंने कहा हमारी सरकार बनते ही 18 लाख आवास से वंचित लोगों को आवास का अधिकार दिलाया, 70 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने एक हजार रुपए पहुंच रहे है इसी तरह छत्तीसगढ़ के हजारों लोगों में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का भी लाभ लिया है।उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा लगातार क्षेत्र का दौरा कर यहां के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चैत्र माह के तेरहवीं तिथि को भोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पिछले वर्ष जब स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने के लिए हमने केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से निवेदन किया था और भोरमदेव महोत्सव के दिन ही हमें भोरमदेव कॉरिडोर की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और आज भूमिपूजन भी सम्पन्न हो गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में भोरमदेव की तरह ही आस्था का केंद्र माने जाने वाले पंचमुखी श्री बुढ़ा महादेव मंदिर का भी अब विकास किया जा रहा है, जिसके लिए विगत दिनों जब आयोजन किया गया तो लोगों ने अपनी पूरी भक्ति भाव से मंदिर के विकास के लिए दिल खोलकर दान किया और एक ही दिन में 75 लाख रुपए कार्यक्रम समाप्ति के पूर्व ही संग्रहित हो गए थे। कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रम में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री श्री तोखन साहू, सांसद श्री संतोष पाण्डेय, पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेषर पटेल, राज्य कृषक कल्याण परिषद् के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रवंशी, पूर्व विधायक डॉ. सियाराम साहू, श्री मोतीराम चंद्रवंशी, श्री अशोक साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, श्री राजेन्द्र चंद्रवंशी, जिला पंचायात उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी, बोड़ला जनपद अध्यक्ष श्रीमती बालका रामकिंकर वर्मा, उपाध्यक्ष श्री नंद श्रीवास, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रामकुमार भट्ट, श्री संतोष पटेल, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती गंगाबाई लोकचंद साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह, श्री विदेशी राम धुर्वे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री अनिल ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, श्री मीलूराम साहू उपस्थित थे।

न्यूज रूटीन

छत्तीसगढ़ का हरित भविष्य और हमारी जिम्मेदारी

14 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर यह याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि ऊर्जा केवल सुविधा का साधन नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की नींव है। प्रदेश में औद्योगिक, कृषि और घरेलू स्तर पर ऊर्जा की खपत हर साल लगभग 15-20 प्रतिशत बढ़ रही है। यदि इस रफ्तार को नियंत्रित नहीं किया गया, तो न केवल बिजली बिल बढ़ेंगे, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी असहनीय हो जाएगा।

क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने कहा कि सतत विकास और पर्यावरण संतुलन के लिए ऊर्जा का विवेकपूर्ण और कुशल उपयोग अनिवार्य है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीएम सूर्यघर योजना जैसी पहलें स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को जन-जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक लगभग 1.2 लाख सौर ऊर्जा उपकरण घरों तक पहुँच चुके हैं, जिससे औसतन प्रति परिवार 20-25 प्रतिशत बिजली बचत संभव हुई है।

समान रूप से, औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता सुधार के उपाय अपनाने से प्रति वर्ष करोड़ों रूपये की बचत हो सकती है और साथ ही कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। उदाहरण के लिए, बिजली बचत तकनीक अपनाने वाले कुछ औद्योगिक प्लांट्स में पिछले दो वर्षों में 18-20 प्रतिशत ऊर्जा की बचत हुई है।

भूपेंद्र सवन्नी ने प्रदेशवासियों से स्पष्ट आह्वान किया कि ऊर्जा संरक्षण केवल सरकारी योजना या नीति का विषय नहीं है। यह हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। छोटे-छोटे प्रयास—जैसे ऊर्जा-सक्षम एलईडी बल्बों का उपयोग, सौर उपकरणों की स्थापना, उपकरणों का समय पर बंद करना—सांस्कृतिक बदलाव ला सकते हैं। यदि हम समय रहते यह कदम नहीं उठाते, तो छत्तीसगढ़ का हरित और स्वच्छ भविष्य खतरे में पड़ सकता है।

सतत विकास और पर्यावरण संतुलन के लिए ऊर्जा का विवेकपूर्ण और कुशल उपयोग अनिवार्य है। यह केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रत्येक घर, प्रत्येक उद्योग, प्रत्येक विद्यालय-सभी को ऊर्जा संरक्षण के प्रति सचेत रहना होगा।

■ भूपेंद्र सवन्नी
क्रेडा अध्यक्ष

'एक सौर पैनल, एक ऊर्जा-सक्षम उपकरण, एक जिम्मेदार नागरिक—यही छोटे कदम मिलकर राज्य को हरित और विकसित बनाएंगे। यदि हम आज जागरूक नहीं हुए, तो भविष्य की पीढ़ियों को भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा,' सवन्नी ने चेतावनी दी।

इस अवसर पर यह भी याद रखना जरूरी है कि ऊर्जा संरक्षण केवल बचत का मामला नहीं है, बल्कि यह रोजगार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास से भी जुड़ा है। ऊर्जा दक्षता से औद्योगिक लागत घटेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा रोजगार पैदा करेगी और पूरे प्रदेश में निवेश-अनुकूल माहौल बनेगा।

छत्तीसगढ़ को हरित और विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य केवल योजनाओं या नीतियों से संभव नहीं है। इसे हर घर, हर उद्योग और हर नागरिक के व्यवहार में उतारना होगा। अगर हम समय रहते ऊर्जा संरक्षण को अपनाएँ, तो हम न केवल बिजली की बचत करेंगे, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करके सतत विकास की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाएँगे।

आज का फैसला–कल का भविष्य- ऊर्जा बचाएँ, प्रकृति बचाएँ, छत्तीसगढ़ को हरित और विकसित बनाएँ।

पाँच शक्तिपीठ - आस्था को सर्किट में बदलने की रणनीति

कुदरगढ़, चन्द्रहासिनी, महामाया रतनपुर, दंतेश्वरी, डोंगरगढ़ की बम्लेश्वरी— इन पाँच शक्तिपीठों को चारधाम की तर्ज़ पर जोड़ने की योजना यह बताती है कि अब छत्तीसगढ़ धार्मिक पर्यटन को बिखरे स्थल नहीं, संगठित शक्ति के रूप में देख रहा है। यह कदम पर्यटन से ज़्यादा संस्कृति आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में है।

जब गांव वैश्विक नक्शे पर आते हैं

धुड़मारास का संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में चुना जाना कोई संयोग नहीं है। यह उस मॉडल की मान्यता है जहाँ पर्यटन स्थानीय जीवन को रौंदता नहीं, सहारा देता है। इसी तरह जशपुर का मधेश्वर पहाड़— दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग— गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना छत्तीसगढ़ को आस्था और एडवेंचर— दोनों मानचित्रों पर स्थापित करता है। ?10 करोड़ की केंद्र सहायता अगर सही दिशा में लगी, तो यह स्थल केदारनाथ या अमरनाथ की तरह सिर्फ़ मंदिर नहीं, अनुभव बन सकता है।

राजिम से चंदखुरी तक - छत्तीसगढ़ की धार्मिक रीढ़

राजिम— जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है, राजीव लोचन मंदिर, कुंभ कल्प— यह सब बताता है कि छत्तीसगढ़ की आस्था नक़्शे में नई नहीं, राजनीति में उपेक्षित रही है। चंदखुरी में माता कौशल्या, शिवरीनारायण में माता शबरी, डोंगरगढ़, रतनपुर, चन्द्रपुर— यह सब मिलकर छत्तीसगढ़ को रामायण और शक्तिपूजा का केंद्रीय भूगोल बनाते हैं।

सिरपुर से सिंघनपुर-इतिहास जो किताबों से बाहर आना चाहता है

सिरपुर— जहाँ चीनी यात्री आए, जहाँ बौद्ध विहार थे, जहाँ शैव, वैष्णव और बौद्ध परंपरा मिली। भोरमदेव— खजुराहो की छाया नहीं, छत्तीसगढ़ की मौलिक शिल्प चेतना। सिंघनपुर और रामगढ़ की गुफाएँ— जहाँ आदिमानव ने चित्र बनाए, जहाँ भारत की सबसे पुरानी नाट्यशाला के संकेत हैं। ये स्थल सिर्फ़ पर्यटन नहीं, इतिहास की राजनीति हैं— जो अब तक राष्ट्रीय विमर्श से बाहर रही।

चित्रकोट से मैनपाट- प्रकृति का आत्मविश्वास

चित्रकोट— भारत का नियाग्रा। तीरथगढ़— जहाँ पानी गिरता नहीं, नृत्य करता है। मैनपाट— छत्तीसगढ़ का शिमला, मिनी तिब्बत। यह सब राज्य की उस क्षमता का संकेत हैं जहाँ पर्यटन भीड़ नहीं, शांति बेच सकता है।

अंतिम सवाल -क्या छत्तीसगढ़ पर्यटन को सिर्फ़ दिखाएगा या जिएगा?

पर्यटन नीति बनाना आसान है। इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना संभव है। लेकिन असली सवाल यह है—

- क्या स्थानीय व्यक्ति सिर्फ़ कर्मचारी रहेगा या साझेदार बनेगा?
- क्या जंगल सिर्फ़ बैकड्रॉप रहेगा
- या संरक्षित जीवन बनेगा?

अगर सरकार इस संतुलन को साध पाती है, तो छत्तीसगढ़ पर्यटन का उपभोक्ता नहीं, पर्यटन का मॉडल बन सकता है। और तब यह कहना गलत नहीं होगा— छत्तीसगढ़ अब सिर्फ़ संसाधनों का राज्य नहीं, संभावनाओं की राजनीति बन चुका है।

यूनेस्को की दहलीज पर सिरपुर

छत्तीसगढ़ की प्राचीन विरासत बनेगी विश्व धरोहर

उल्लेखनीय है कि सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर/श्रिपुरा है जो महानदी के तट पर बसी एक प्राचीन नगरी है, जिसका इतिहास 5वीं से 12वीं सदी तक फैला हुआ है। यह दक्षिण कोसल का प्रमुख राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है और यहां हिंदू, बौद्ध व जैन तीनों धर्मों के तीर्थ, मठ, मंदिर और विहारों का दुर्लभ संग्रह मिलता है।

छत्तीसगढ़ का प्राचीन रत्न सिरपुर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में प्रवेश करने को तैयार है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने नामांकन प्रक्रिया को रफ्तार दी है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दौरे ने इसे केंद्र स्तर पर अपरिहार्य बना दिया है। नए वर्ष में अंतिम स्वीकृति की मजबूत संभावना है, जो राज्य को पहला विश्व धरोहर स्थल प्रदान करेगा। छठी शताब्दी से बहुधार्मिक शहरी केंद्र के रूप में प्रसिद्ध सिरपुर में बौद्ध, जैन, हिंदू और शैव-वैष्णव परंपराएं एक साथ विकसित हुईं। यहां लक्ष्मण मंदिर, बुद्ध विहार, प्राचीन आवासीय परिसर, बाजार और नदी घाटों सहित 125 से अधिक खुदाई स्थल मौजूद हैं, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से दस्तावेजित किया है। यूनेस्को टैग के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय मानकों सुरक्षा, प्रस्तुति और आगंतुक प्रबंधन को पूरा करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य पर्यटन एजेंसियों ने सिरपुर का विस्तृत निरीक्षण पूरा कर लिया है। यह रिपोर्ट केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को प्रस्ताव को मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है, जिसमें नवंबर 2025 तक सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट शामिल है।

01 जनवरी 2026 को श्री शेखावत ने उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के साथ सिरपुर का दौरा किया। उन्होने लक्ष्मण देवालय, आनंद प्रभु कुटी विहार, तीवरदेव विहार, सुरंग टीला और हाट बाजार का निरीक्षण कर निर्देश दिए कि मूल संरचना सुरक्षित रखें और कनेक्टिविटी बढ़ाएं। श्री शेखावत ने कहा कि सिरपुर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने का प्रयास जारी है। उन्होने आगे कहा कि सिरपुर एक ऐतिहासिक नगर है, जो कभी इस प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, सिरपुर में आकर यहां की पुरासंपदा को देखना, एक हजार साल की यहां की विकास यात्रा को देखना समझना और इस गौरवशाली अतीत को अनुभव करना निश्चित रूप से मन मे, शरीर में एक स्पंदन पैदा करता है। यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि इन सब का दर्शन करने का, अपने पुरखों के इतिहास और उनके गौरव को देखने और समझने का अवसर मिला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का यह स्थान देश में स्थित 140 केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों में से एक है, जिसके संरक्षण के लिए यहां के पुरासंपदा का

रखरखाव हो सके इसके लिए भारत सरकार व राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र की और इस जगह की जितनी महत्ता है, उसके अनुरूप अभी यहां पर्यटन विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। मैं पर्यटन मंत्री होने के नाते कह सकता हूं कि इस जगह को यदि ठीक से कनेक्टिविटी दी जाए और ठीक से यहां पर्यटन की मूलभूत सुविधाएं का विकास किया जाए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ पर्यटन की दृष्टि से एक नया स्वरूप प्राप्त करेगा। छत्तीसगढ़ की पहचान एक समृद्ध, ऐतिहासिक विरासत, प्राकृतिक संपदा वाले प्रदेश के रूप में बन रही है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ पर्यटन गतिविधियों का केन्द्र बने इस दृष्टिकोण से सिरपुर बहुत महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय पर्यटन मंत्री का यह दौरा राज्य सरकार की रिपोर्ट को मजबूत करता है, क्योंकि सिरपुर 140 संरक्षित स्मारकों में शुमार है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सिरपुर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा है। यूनेस्को मान्यता से वैश्विक पहचान मिलेगी, पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं के लिए हजारों रोजगार सृजित होंगे। उनके निर्देश पर सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ 125 खुदाई स्थलों का मास्टर प्लान तैयार किया। इसमें लक्ष्मण मंदिर, आनंद प्रभु कुटी विहार, तीवरदेव विहार, सुरंग टीला, गंधेश्वर मंदिर सहित प्रमुख साइटें शामिल हैं। नवंबर 2025 की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रालय पहुंच चुकी है, दिसंबर में अंतिम समीक्षा हुई।

वहीं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा की सिरपुर को वैश्विक पर्यटन हब बनाएंगे। बैटरी ई-कार्ट, 3डी इंटरप्रेटेशन सेंटर, होमस्टे क्लस्टर, हेरिटेज शटल और गाइडेड वॉक शुरू हो रहे हैं। चार हेरिटेज सर्किट, बौद्ध विहारों से लक्ष्मण मंदिर तक जोड़ेंगे। सड़क उन्नयन, डिजिटल साइनेज, स्वच्छता और सर्किट मैनेजमेंट पर कार्य किया जा रहा है । स्थानीय लाभ के लिए गाइड ट्रेनिंग, हस्तशिल्प बाजार और ईको-फ्रेंडली स्टे पर जोर दिया जाएगा।

सिरपुर दक्षिण कोसल की राजधानी थी

उल्लेखनीय है कि सिरपुर दक्षिण कोसल की राजधानी थी। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का सबसे प्रसिद्ध और पुरातन हिंदू मंदिर है, जो 6वीं–7वीं सदी में बनाया गया था। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और प्रमुख रूप से लाल ईंटों से निर्मित है। रानी वासटादेवी ने इसे अपने पति राजा हर्षगुप्त की स्मृति में बनवाया था इसे एक प्रेम कथा का प्रतीक भी माना जाता है। तिवरदेव विहार एक प्राचीन बौद्ध विहार है, जो 7वीं–8वीं सदी का बताया जाता है। यह बड़े पैमाने पर ईंटों का बना हुआ था और खुदाई में इसका अवशेष मिला है। बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा यह विहार सिरपुर में बुद्ध के अनुयायियों द्वारा ध्यान, शिक्षा और धार्मिक क्रियाओं के लिए उपयोग में लाया गया था। आनंद प्रभु कुटी विहार सिरपुर का एक प्रमुख बौद्ध स्थल है, जिसे भिक्षु आनंद प्रभु द्वारा स्थापित किया गया था। यह विहार 14 कमरे वाला एक बड़ा बौद्ध मठ है, जिसमें एक मुख्य प्रवेश द्वार और सुंदर नक्काशीदार स्तंभ पाए गए हैं। यहां बुद्ध की एक विशाल मूर्ति और अन्य बौद्ध प्रतिमाएँ मिलती हैं। सुरंग टीला सिरपुर का एक अनोखा पुरातात्विक स्थल है, जिसमें प्राचीन काल के मंदिर के अवशेष मिले हैं। यह 7वीं सदी का मंदिर था, जिसमें 5 गर्भगृह पाए गए हैं। इन गर्भगृहों में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा स्थित है, जो इस धार्मिक स्थल की विविधता को दर्शाता है।

यह हिंदू–बौद्ध–जैन का दुर्लभ मिश्रण है जिसकी तुलना अंगकोरवाट या बोधगया से किया जा सकता है। संयुक्त सांस्कृतिक–प्राकृतिक श्रेणी में भारत के 44 विश्व धरोहरों में छत्तीसगढ़ का प्रवेश सिरपुर से होगा। यूनेस्को टैग से वैश्विक फंडिंग, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दस हजार से अधिक रोजगार और 500 करोड़ का पर्यटन राजस्व संभावित है। उल्लेखनीय है कि सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर/श्रिपुरा है जो महानदी के तट पर बसी एक प्राचीन नगरी है, जिसका इतिहास 5वीं से 12वीं सदी तक फैला हुआ है। यह दक्षिण कोसल का प्रमुख राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है और यहां हिंदू, बौद्ध व जैन तीनों धर्मों के तीर्थ, मठ, मंदिर और विहारों का दुर्लभ संग्रह मिलता है। खुदाई में यहां 22 शिव मंदिर, 5 विष्णु मंदिर, 10 बुद्ध विहार और 3 जैन विहार के अवशेष मिले हैं।

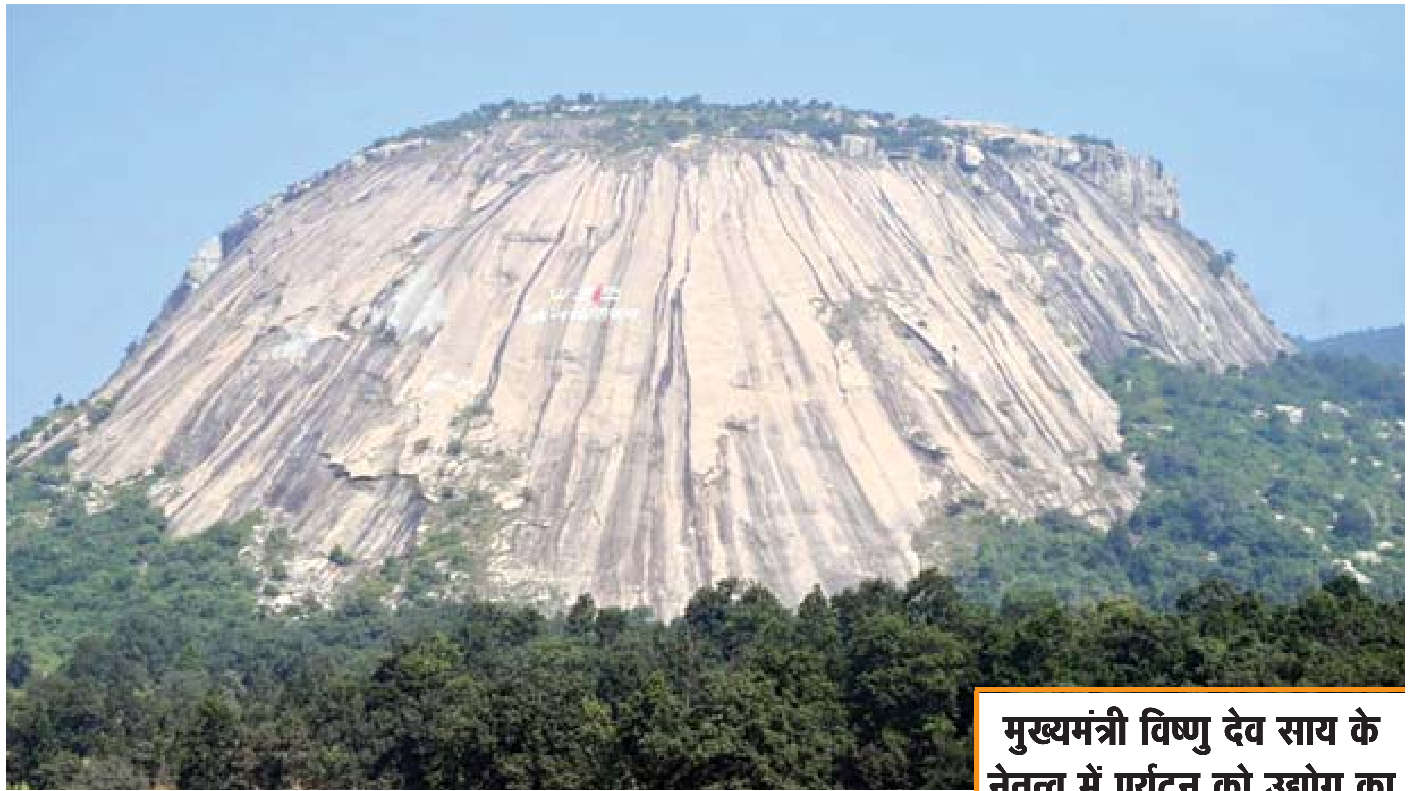

पर्यटन को उद्योग बनाना छत्तीसगढ़ का साहसिक दांव

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, तो यह फैसला सिर्फ़ आर्थिक नहीं, राजनीतिक रूप से भी निर्णायक माना जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ उन गिने-चुने राज्यों में है जहाँ प्रकृति ने राजनीति से पहले निवेश कर दिया था। विशाल वन,अविरल नदियाँ, प्राकृतिक जलप्रपात, हज़ारों साल पुरानी आस्था और सभ्यता— यह सब यहाँ पहले से मौजूद था। कमी सिर्फ़ एक थी— राज्य की दृष्टि। अब हाल के वर्षों में जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, तो यह फैसला सिर्फ़ आर्थिक नहीं, राजनीतिक रूप से भी निर्णायक माना जाना चाहिए। क्योंकि पर्यटन को उद्योग मानना यह स्वीकार करना है कि—

- **जंगल बोझ नहीं हैं**
- **आदिवासी संस्कृति बाधा नहीं है**
- **और आस्था पिछड़ापन नहीं है**

ईको-टूरिज्म : विकास बनाम विनाश की बहस का व्यावहारिक उत्तर

छत्तीसगढ़ में वर्षों से एक बहस रही— जंगल बचाएँ या रोज़गार दें? ईको-टूरिज्म ने

इस बहस को नारे से निकालकर नीति में बदलने की कोशिश की है। वनांचल में रिसॉर्ट, होटल चेन, और सबसे महत्वपूर्ण— होम-स्टे पॉलिसी। यह सिर्फ़ पर्यटक को ठहराने की व्यवस्था नहीं, यह स्थानीय आदिवासी को पर्यटन का भागीदार बनाने की राजनीति है। अगर यह नीति ईमानदारी से लागू हुई, तो छत्तीसगढ़ 'प्रोजेक्ट बनाम विस्थापन' की पुरानी राजनीति से बाहर आ सकता है।

राम वन गमन पथ - आस्था का सांस्कृतिक पुनर्संयोजन

छत्तीसगढ़ को अक्सर धार्मिक पर्यटन के नक्शे में हाशिए पर रखा गया। जबकि सच्चाई यह है कि प्रभु श्रीराम ने अपने वनवास के दस वर्ष इसी धरती पर बिताए। कोरिया के सीतामढ़ी-हरचौका से सुकमा के रामाराम तक राम वन गमन पथ का विकास केवल धार्मिक परियोजना नहीं है। यह उस ऐतिहासिक उपेक्षा का सांस्कृतिक प्रत्युत्तर है जिसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका रामकथा में दबा दी गई थी। यह आस्था का राजनीतिकरण नहीं, बल्कि इतिहास का पुनर्स्थापन है।

जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय मे देश-विदेश के पर्यटक आ रहे हैं

उद्घाटन के महज दो महीनों में 72 हजार से अधिक लोग पहुंचे संग्रहालय

नवा रायपुर के आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में अंग्रेजी हुकुमत के दौरान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बने शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय अपने उद्देश्यों में सार्थक कर रहा है। संग्रहालय को देखने देश-विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, वहीं संग्रहालय विद्यार्थियों-शोधार्थियों सहित आम लोगों के लिए प्रेरणा और ज्ञान का केन्द्र बन रहा है।

स्कूलों और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के साथ ही बड़ी संख्या में आमजन संग्रहालय को देखने पहुंच रहे हैं। उद्घाटन के बाद लगभग दो महीनों के अंतराल में ही 72 हजार से अधिक दर्शक ने संग्रहालय का अवलोकन कर चुके है।

गौरतलब है कि आदिम जाति विकास विभाग के मार्गदर्शन में जनजातीय संस्कृति परंपराओं पर आधारित म्यूजियम तथा शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी म्यूजियम का निर्माण तेजी के साथ पूरा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और विभागीय मंत्री श्री राम विचार द्वारा भी निर्माण कार्यो की सतत निगरानी और दिशा-निर्देश दिए गए।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्योत्सव रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 01 नवम्बर को इस भव्य संग्रहालय को लोगों को समर्पित किया गया। आगन्तुकों के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह-जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय आकर्षण और उत्साह का केंद्र बना हुआ है।

जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान की मिलती है जानकारी

आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय वर्गों के ऐतिहासिक गौरव गाथा, शौर्य और बलिदान का प्रतीक शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह-जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हाथों उद्घाटन होना गौरव की बात है। श्री बोरा ने कहा कि काफी संख्या में लोग संग्रहालय देखने आ रहे हैं, इससे संग्रहालय बनाने का उद्देश्य सार्थक हो रहा है। विशेषकर छुट्टियों और त्यौहारों के दिनों में लोग बड़ी संख्या में संग्रहालय आते हैं, विभाग द्वारा भी आगंतुकों के हिसाब से सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। दर्शकों को जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान संबंधी जानकारी के लिए गाइड की भी व्यवस्था की गई है। संग्रहालय पूरी तरह से डिजिटली है। संग्रहालय के अंदर मॉनीटर पर दिये गए क्यू आर कोड स्कैन कर तथा माइक्रोफोन के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही दिव्यांगों, महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्हीलचेयर व शिशुवती महिलाओं के लिए शिशु देख-रेख कक्ष बनायी गई है। इस संग्रहालय के शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने लगा है।

श्री बोरा ने कहा कि संग्रहालय का धरातल में आने से नई पीढ़ियों को अपने पुरखों की वीरता और साहस को याद दिलाता रहेगा। यह न सिर्फ जनजातीय वर्गों के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए प्रेरणाप्रद है।

देश के विभिन्न राज्यों तथा विदेशों से भी पर्यटक आ रहे हैं संग्रहालय देखने

संग्रहालाध्यक्ष डॉ. अनिल वीरूलकर ने बताया कि संग्रहालय देखने आने वाले दर्शकों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। संग्रहालय में प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों तथा विदेशों से भी पर्यटक आ रहे हैं। हाल ही में नीदरलैंड के पर्यटकों का दल जनजातीय संग्रहालय देखने आये थे उन लोगों ने भी इस डिजिटल संग्रहालय की काफी प्रशंसा की।

पिछले माह नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने भी संग्रहालय का भ्रमण कर काफी सराहना की है। इसके साथ ही सेना के अधिकारी, प्रशासनिक प्रशिक्षु अधिकारी स्कूल, कॉलेज के छात्र-छात्राएँ बड़ी संख्या में आ रहे हैं।

संग्रहालय पूरी तरह सीसीटीवी से लैस

संग्रहालय परिसर में पर्यटकों व आगंतुकों के हिसाब से शुद्ध पेयजल, पार्किंग, शौचालय तथा सूचना केंद्र की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। संग्रहालय पूरी तरह सीसीटीवी से लैस है। इसके साथ ही प्राथमिक उपचार केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

संग्रहालय बेहद आकर्षक एवं जीवंत

झारखण्ड रांची से संग्रहालय देखने आए इस्लाम अंसारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर बने स्मारक संग्रहालय बेहद आकर्षक एवं जीवंत है। जीवंत इस्टेच्यु देख कर लगता है कि हम तत्कालीन समय में आ गये हैं। इन जीवंत प्रस्तुतियों से हमें उस काल की स्मृतियां महसूस होने लगती है।

नवा रायपुर से ही दोस्तों के साथ आए 11 वीं के छात्रगण मयंक, शनी और आयूष ने कहा कि संग्रहालय मनोरंजन के साथ ही ज्ञानवर्धक भी है। इस संग्रहालय में अपने महापुरूषों और बलिदानियों के जीवत गाथा को देखकर गर्व महसूस हो रहा है।

गिद्ध संरक्षण में छत्तीसगढ़ की नई उड़ान

इंद्रावती टाइगर रिजर्व बना देश का मॉडल

मध्य भारत के सबसे स्वच्छ नदी-वन पारिस्थितिकी तंत्रों में शामिल इंद्रावती टाइगर रिजर्व अब केवल बाघों और जंगली भैंसों का ही नहीं, बल्कि विलुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है।

छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व ने गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में देशभर के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। मध्य भारत के सबसे स्वच्छ नदी-वन पारिस्थितिकी तंत्रों में शामिल यह रिजर्व अब केवल बाघों और जंगली भैंसों का ही नहीं, बल्कि विलुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है।

गिद्ध पर्यावरण के 'सफाईकर्मी'

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार इंद्रावती के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में गिद्धों सुरक्षित क्षेत्रों का निर्माण कर इनकी घटती आबादी को बचाना और बढ़ाना है, क्योंकि गिद्ध पर्यावरण के 'सफाईकर्मी' हैं और इनके बिना बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। गिद्धों के अस्तित्व पर जहरीली दवाओं, असुरक्षित शव निपटान और मानव हस्तक्षेप जैसे गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व में उपग्रह (सैटेलाइट) टेलीमेट्री आधारित निगरानी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

गिद्ध लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं सक्रिय

छत्तीसगढ़ में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है, जिसमें उच्च-रिज़ॉल्यूशन गिद्ध गतिविधि डेटा का उपयोग संरक्षण कार्यों की दिशा तय करने के लिए किया जा रहा है। अब तक के आंकड़ों से पता चला है कि गिद्ध लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और घने जंगलों व मानव बस्तियों के बीच लगातार आवाजाही करते हैं।

वन्यजीव प्रबंधन को मिली नई वैज्ञानिक दिशा

गौरतलब है कि वर्ष 2022 से 2025 के बीच गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। राज्य में पहली बार दो गिद्धों की सैटेलाइट ट्रैकिंग के माध्यम से 18,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले GPS डेटा पॉइंट्स प्राप्त किए गए हैं, जिससे वन्यजीव प्रबंधन को नई वैज्ञानिक दिशा मिली है। इस सफलता में क्षेत्रीय जीवविज्ञानी श्री सूरज कुमार के नेतृत्व में 'गिद्ध मित्र दल' (गिद्ध संरक्षण स्वयंसेवक दल) की अहम भूमिका रही है। यह दल घोंसलों की निगरानी, शवों के सुरक्षित प्रबंधन और स्थानीय समुदायों को संरक्षण से जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसी सामुदायिक सहयोग का परिणाम है कि 'गुड्डा सारी गुट्टा' जैसे दुर्गम क्षेत्रों में पहली बार निर्बाध प्रजनन सुनिश्चित हो सका है।

वुल्चर रेस्टोरेंट की स्थापना

संरक्षण प्रयासों के तहत उप-निदेशक श्री संदीप बलागा के पर्यवेक्षण में 'वुल्चर रेस्टोरेंट' की स्थापना भी की गई है। यह नियंत्रित भोजन स्थल हैं, जहां केवल पशु चिकित्सा परीक्षण के बाद NSAID-मुक्त शव ही रखे जाते हैं। इससे गिद्धों को सुरक्षित भोजन मिल रहा है। साथ ही ये केंद्र सामुदायिक शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, जहां स्कूलों और स्थानीय युवाओं को पारिस्थितिकी तंत्र में गिद्धों के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है।

प्रगति प्लेटफार्म बना गेमचेंजर

बीएसपी आधुनिकीकरण और लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मिली नई गति

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की गति नई ऊँचाइयों पर पहुँची है। दशकों से लंबित महत्वपूर्ण अधोसंरचना एवं ऊर्जा परियोजनाएँ अब 'प्रगति' प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से समयबद्ध ढंग से पूरी हो रही हैं। यह केंद्र सरकार की परिणामोन्मुख, जवाबदेह तथा निर्णायक कार्यशैली का सशक्त प्रमाण है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 'प्रगति' प्लेटफ़ॉर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण से न केवल देश में रेल उत्पादन को नई गति मिली है, बल्कि इससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती मिली है और औद्योगिक विकास को नई दिशा प्राप्त हुई है।

इसी प्रकार एनटीपीसी की लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना (1600 मेगावाट) से छत्तीसगढ़ सहित छह राज्यों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है तथा औद्योगिक और कृषि गतिविधियों को नई ऊर्जा प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 'प्रगति' प्लेटफ़ॉर्म ने परियोजनाओं की निगरानी, निरंतर समीक्षा और बाधाओं के त्वरित समाधान की एक सशक्त प्रणाली विकसित की है। स्पष्ट लक्ष्य, तेज़ क्रियान्वयन और ठोस परिणाम—यही नए भारत की कार्यसंस्कृति है और यही 'विकसित भारत - 2047' के लक्ष्य को साकार करने का मार्ग है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित प्रगति (PRAGATI) की 50वीं बैठक ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को भी नई गति प्रदान की है। प्रगति सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए विकसित एक आईसीटी आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसने परियोजनाओं की निगरानी और समाधान की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया है। पिछले दशक में प्रगति प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से 85 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाओं की रफ्तार तेज हुई है। इससे देशभर में अवसंरचना, ऊर्जा, रेल, सड़क, कोयला और अन्य क्षेत्रों से जुड़े अनेक कार्यों को समयबद्ध प्रगति मिली है। इन परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएँ भी शामिल हैं।

बैठक में भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इस परियोजना को वर्ष 2007 में स्वीकृति मिली थी। प्रगति बैठकों में नियमित समीक्षा और अंतर-एजेंसी समन्वय के कारण इस परियोजना को नई गति मिली, जिसके परिणामस्वरूप इसका कार्य तेज़ी से आगे बढ़ा और लक्षित प्रगति सुनिश्चित हुई।

भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण से उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, सहायक उद्योगों के विस्तार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। इससे राज्य को देश के प्रमुख इस्पात उत्पादन केंद्र के रूप में और अधिक मजबूती मिली है।

इसी प्रकार रायगढ़ में वर्ष 2009 में स्वीकृत लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना की प्रगति प्लेटफ़ॉर्म के अंतर्गत उच्च स्तरीय समीक्षाओं, समय-समय पर दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देशों और निरंतर मॉनिटरिंग से तेज गति मिली और इसके क्रियान्वयन में ठोस प्रगति दर्ज की गई।

आज लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाली प्रमुख परियोजनाओं में से एक बन चुकी है। इस परियोजना ने न केवल बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाई है, बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान को 'पावर हब ऑफ इंडिया' के रूप में और अधिक मजबूत किया है। इससे राज्य और देश दोनों के ऊर्जा तंत्र को नई स्थिरता प्राप्त हुई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह रेखांकित किया कि प्रगति प्लेटफ़ॉर्म ने सहयोगी संघवाद को नई शक्ति दी है और केंद्र तथा राज्यों के संयुक्त प्रयासों से विकास कार्यों में गति और विश्वास दोनों बढ़ा है।

प्रगति से तेज़ होती छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रगति की 50वीं बैठक को देश और छत्तीसगढ़ के लिए दूरगामी महत्व का बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने की जो व्यवस्था स्थापित की गई है, उसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिला है। उन्होंने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण तथा लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना जैसी बड़ी परियोजनाओं को नई गति मिलना इस बात का प्रमाण है कि प्रगति प्लेटफ़ॉर्म ने वास्तविक अर्थों में समाधान-उन्मुख शासन का मॉडल प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से प्रदेश के औद्योगिक विकास, ऊर्जा क्षमता, निवेश, रोज़गार और सहायक अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रगति के माध्यम से परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही सुनिश्चित होने से छत्तीसगढ़ विकसित भारत ञ 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य में अपनी निर्णायक भूमिका और मजबूती के साथ निभाता रहेगा।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने रचा आवास क्षेत्र में नया कीर्तिमान

हाउसिंग बोर्ड के इतिहास में पहली बार एक वर्ष में 1022 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों का विक्रय

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने वर्ष 2025 में आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों के विक्रय के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मंडल द्वारा जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच कुल 4689 संपत्तियों का विक्रय किया गया, जिनका कुल मूल्य 1022 करोड़ रुपये से अधिक है। यह छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के गठन के बाद अब तक का सर्वाधिक वार्षिक विक्रय है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव के नेतृत्व में मंडल द्वारा किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने की दिशा में योजनाबद्ध एवं प्रभावी कार्य किया जा रहा है, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम इस अभूतपूर्व सफलता के रूप में सामने आया है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रारंभ से ही समाज के कमजोर एवं निम्न आय वर्ग को प्राथमिकता दी जाती रही है। अब तक निर्मित कुल आवासों में लगभग 70 प्रतिशत आवास कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए बनाए गए हैं। विगत पांच वर्षों में जहां मंडल द्वारा औसतन 1387 संपत्तियों का प्रतिवर्ष विक्रय हुआ और औसत मूल्य लगभग 262 करोड़ रुपये रहा, वहीं वर्ष 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 4689 संपत्तियों एवं 1022 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह मंडल की कार्यप्रणाली में हुए सुधार, नीतिगत सरलीकरण और आम नागरिकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

विगत एक वर्ष के दौरान शासन द्वारा लागू की गई ओटीएस-2 (वन टाइम सेटलमेंट) योजना के तहत हितग्राहियों को 30 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप 1452 संपत्तियों का विक्रय हुआ। इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 220.16 करोड़ रुपये रहा, जिससे मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के बड़ी संख्या में नागरिकों को सीधा लाभ मिला।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर इस वर्ष 23 से 26 नवंबर 2025 तक रायपुर के बीटीआई ग्राउंड, शंकर नगर में आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला 2025 भी अत्यंत सफल रहा।

इस मेले के दौरान छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा 26 जिलों में 2080 करोड़ रुपये की लागत वाली 56 नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया। साथ ही मेले के दौरान ही 305 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का विक्रय हुआ, जिससे मंडल की योजनाओं के प्रति आमजन का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2025 में 1022 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों का विक्रय एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह सरकार की जनहितैषी नीतियों और आम नागरिकों के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव तथा मंडल के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस सफलता के लिए बधाई दी।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री **ओ.पी. चौधरी** ने कहा कि एक वर्ष में 1022 करोड़ रुपये की संपत्तियों का विक्रय राज्य के आवास क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह मुख्यमंत्री की जनकल्याणकारी सोच, स्पष्ट आवास नीति तथा हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता का परिणाम है। शासन का लक्ष्य प्रत्येक पात्र नागरिक को किफायती, सुलभ और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री **अनुराग सिंह देव** ने कहा कि वर्ष 2025 की यह सफलता मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के मार्गदर्शन, मंत्री श्री ओपी चौधरी के नेतृत्व और मंडल की पूरी टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि मंडल पारदर्शिता, नई सोच और जनहित को केंद्र में रखकर कार्य कर रहा है तथा भविष्य में भी आवासहीनों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा।

नदी-नाले पार कर बचाया गया भविष्य

'बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़' अभियान को मिल रही जमीनी मजबूती

राज्य सरकार द्वारा संचालित 'बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़' अभियान जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से साकार होता नजर आ रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला प्रशासन की सतर्कता और संवेदनशीलता के चलते दुर्गम एवं पहुँचविहीन क्षेत्र में नदी-नाले पार कर 12 वर्षीय बालिका का बाल विवाह समय रहते रोका गया। इस त्वरित कार्रवाई से न केवल एक मासूम का भविष्य सुरक्षित हुआ, बल्कि समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरुद्ध सशक्त संदेश भी गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 02 जनवरी 2026 को प्रशासन को सूचना मिली कि सुकमा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रामाराम के सुदूर गांव नाड़ीगुफा में एक नाबालिक बालिका का विवाह किया जा रहा है। सूचना की गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के मार्गदर्शन में तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के नेतृत्व में जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन तथा विभागीय अमले की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने उफनते नदी-नालों और अत्यंत दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद पैदल यात्रा कर गांव तक पहुँच बनाई और समय रहते विवाह प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया।

मौके पर यह पाया गया कि पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं। अधिकारियों द्वारा संवेदनशीलता के साथ परिजनों एवं ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों, कानूनी दायित्वों तथा इसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। प्रशासन की समझाइश का सकारात्मक प्रभाव पड़ा और परिजनों ने स्वेच्छा से बाल विवाह रोकने का निर्णय लिया। ग्रामीणों की उपस्थिति में विधिवत पंचनामा तैयार कर कार्रवाई को औपचारिक रूप दिया गया।

कार्रवाई के दौरान बालिका को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने तथा उसके सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य के लिए परिजनों को प्रेरित किया गया। साथ ही शासन की विभिन्न बाल संरक्षण एवं शिक्षा से संबंधित योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा 10 मार्च 2024 को 'बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़' अभियान का शुभारंभ किया गया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 13,823 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप नवंबर 2025 तक प्रदेश में 189 बाल विवाह रोके जा चुके हैं। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों एवं जनसहभागिता के चलते बालोद जिला पूर्णतः बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है, जो पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत है। वर्ष 2025-26 के लिए राज्य शासन ने 31 मार्च 2026 तक राज्य की 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने तथा 31 मार्च 2029 तक छत्तीसगढ़ को पूर्णतः बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने स्पष्ट किया है कि बच्चों का सुरक्षित, शिक्षित एवं गरिमामय भविष्य सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं के उन्मूलन हेतु प्रशासनिक सतर्कता, जनजागरूकता एवं त्वरित कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग और सेवादान आरोग्य फाउंडेशन के बीच हुआ एमओयू

अस्पताल की दहलीज पर अब परिजनों को मिलेगा घर जैसा सुकून

राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए बनेंगे विश्राम गृह

जब कोई गंभीर बीमारी घर में दस्तक देती है, तो पूरा परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से टूट जाता है। ऐसे वक्त में दूर-दराज के गांवों से शहर आने वाले गरीब परिवारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इलाज के साथ-साथ खुद के ठहरने की होती है। अक्सर मरीज तो वार्ड में इलाज करा रहा होता है, लेकिन उसके अपने लोग अस्पताल के गलियारों, ठंडी सीढ़ियों या खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने को मजबूर होते हैं। इसी मानवीय पीड़ा को महसूस करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम उठाया है। अब राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के परिजनों के लिए सर्वसुविधायुक्त 'विश्राम गृह' बनाए जाएंगे, ताकि किसी भी मजबूर आंख को रात बिताने के लिए सुरक्षित छत की तलाश में भटकना न पड़े।

इस नेक काम को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में मंत्रालय नवा रायपुर में मेडिकल एजुकेशन विभाग और सेवादान आरोग्य फाउंडेशन के बीच एक एमओयू संपादित हुआ है। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री खुशवंत साहेब , स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त श्री रितेश अग्रवाल सहित सेवादान फाउंडेशन के सदस्य उपस्थित थे।

इस समझौते की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इन आश्रय स्थलों के निर्माण, सजावट और उनके रोजमर्रा के संचालन का पूरा जिम्मा संस्था खुद उठाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार और संस्था मिलकर एक ऐसा मानवीय ढांचा तैयार कर रहे हैं जहाँ परिजनों को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहद किफायती ठहराव मिलेगा। इन विश्राम गृहों में केवल सिर छुपाने की जगह ही नहीं मिलेगी, बल्कि अपनों की सेवा में लगे लोगों के लिए 24 घंटे सुरक्षा, सीसीटीवी की निगरानी, साफ-सुथरा भोजन और एक गरिमामय माहौल भी सुनिश्चित किया जाएगा।

योजना के पहले पड़ाव में रायपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और जगदलपुर जैसे प्रमुख शहरों के मेडिकल कॉलेजों को चुना गया है, जहां दूरस्थ अंचलों से बड़ी संख्या में लोग उम्मीद लेकर पहुँचते हैं। यह पहल दिखाती है कि स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ दवा और डॉक्टर तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें उन लोगों के लिए भी जगह होनी चाहिए जो अपने बीमार परिजनों के लिए संबल बनकर साथ खड़े रहते हैं। यह कदम न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि उन हजारों परिवारों को एक बड़ी मानसिक राहत भी पहुँचाएगा जिनके पास शहर में रहने का कोई ठिकाना नहीं होता।

बड़ा सहारा साबित होगी

राज्य सरकार का उद्देश्य केवल बेहतर इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि मरीजों के साथ आने वाले परिजनों की गरिमा और सुविधा का भी ख्याल रखना है। दूर-दराज़ से आने वाले लोग कई दिनों तक अस्पतालों के आसपास असुविधाजनक परिस्थितियों में रुकने को मजबूर होते हैं। विश्राम गृह की व्यवस्था उनके लिए सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती ठहराव का बड़ा सहारा साबित होगी। यह पहल संवेदनशील और उत्तरदायी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विश्राम गृहों के माध्यम से मरीज परिजनों को सम्मानजनक आवास, भोजन और बुनियादी सुविधाएँ एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मानवता और संवेदना का समन्वय और सुदृढ़ होगा।

- विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री

'नो प्रॉफिट-नो लॉस' के आधार पर संचालित होंगे

इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं, अपनों के साथ और सुकून से भी होता है छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को नया विस्तार मिलने जा रहा है। इस एमओयू के तहत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के परिजनों के लिए बेहतर और सुविधाजनक 'विश्राम गृह' बनेंगे जो 'नो प्रॉफिट-नो लॉस' के आधार पर संचालित होंगे।

श्याम बिहारी जायसवाल
स्वास्थ्य मंत्री

संगठन, रणनीति और सत्ता संतुलन का नया अध्याय

नितिन नबीन बनाए गए भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन और नेतृत्व में एक ऐसा कदम उठाया है, जो केवल पदोन्नति या औपचारिक नामकरण तक सीमित नहीं है। यह कदम संकेत है, रणनीति है और एक राजनीतिक संदेश भी –युवा नेतृत्व को मौका देने और संगठन को नए जोश के साथ चुनावी तैयारियों के लिए तैयार करने का। 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन का नाम आज पार्टी के भीतर एक नए यथार्थ का प्रतीक बन गया है।

पार्टी ने नितिन नबीन को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर न केवल संगठन की मजबूती का संदेश दिया है, बल्कि यह स्पष्ट संकेत भी दिया है कि अब भाजपा में युवा नेतृत्व को अवसर देने की नीति सिरे चढ़कर लागू हो रही है। 45 साल की उम्र में पार्टी के अब तक के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले नबीन की नियुक्ति, सिर्फ औपचारिक पदोन्नति नहीं है; यह एक रणनीतिक सोच का प्रतीक है जो चुनावी तैयारियों, संगठनात्मक स्थिरता और क्षेत्रीय संतुलन के आयामों को समेटे हुए है।

नबीन के पास लगभग दो दशकों का अनुभव है, जिसमें चुनावी जिम्मेदारियों का सीमित अनुभव शामिल है। वे ऐसे नेता हैं जो जमीन पर उतरकर संगठन का काम समझते हैं। उनके कार्य का दायरा सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहा; संगठन की नीतियों को लागू करना, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन, और स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना यह सब उनके नेतृत्व की विशेषता रही है।

नबीन केवल एक युवा नेता नहीं हैं। वे मेहनती, राजनीतिक रूप से जिज्ञासु और पूरी तरह समर्पित संगठनात्मक कार्यकर्ता हैं। भाजपा के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि नबीन सरल और पहुंच योग्य नेता हैं, जो वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल स्थापित करने में माहिर हैं। यही कारण है कि उनकी नियुक्ति सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक महत्व रखती है।

लीडरशिप ट्रांजिशन

भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन की पटकथा अब साफ दिखने लगी है। नितिन नबीन को पार्टी का नया वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर भाजपा ने संकेत दे दिया है कि अगला बड़ा चेहरा कौन हो सकता है। पार्टी इतिहास में वे इस पद पर पहुंचने वाले केवल दूसरे नेता हैं। उनसे पहले यही जिम्मेदारी मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को मिली थी।

दिलचस्प यह है कि भाजपा के संविधान में 'वर्किंग प्रेसिडेंट' नाम का कोई पद मौजूद नहीं है। इसके बावजूद 2019 के बाद यह पद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले का सबसे अहम पड़ाव बन गया है। पार्टी के भीतर इसे अब 'ट्रेनिंग ग्राउंड' माना जाता है, जहां अगला अध्यक्ष संगठन की कमान

केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई जामगांव एम

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को नया बल

केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई (CPU) ग्रामीण रोजगार में वनोपज और औषधीय पौधों के संग्रह, प्रसंस्करण और मूल्य-वर्धन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीणों, खासकर महिलाओं, के लिए आय और रोजगार के नए अवसर पैदा करती है। दुर्ग जिला के पाटन विकासखंड के जामगांव एम में स्थापित केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई ग्रामीण रोजगार, वनोपज प्रसंस्करण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड' के नाम से बाजार में उपलब्ध

यह इकाई लगभग 111 एकड़ क्षेत्र में विकसित की गई है, जहां छत्तीसगढ़ शासन और राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के माध्यम से वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों से वनोपज और औषधीय पौधों का क्रय, संग्रहण और प्रसंस्करण किया जा रहा है। यहां तैयार किए जा रहे हर्बल उत्पाद 'छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड' के नाम से बाजार में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है।

प्रसंस्करण इकाई से मिल रहा स्थानीय लोगों को रोजगार

प्रसंस्करण इकाई क्रमांक- 01 में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। यहां आंवला, बेल और जामुन से जूस, कैंडी, लच्छा, मुरब्बा, शरबत, पल्प और आरटीएस पेय जैसे शुद्ध हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों का विक्रय एनडब्ल्यूएफपी मार्ट और संजीवनी स्टोर के माध्यम से किया जाता है। इस इकाई ने मात्र एक वर्ष में लगभग 44 लाख रुपये मूल्य के उत्पादों का निर्माण और विक्रय कर स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने में अहम योगदान दिया है।

20 हजार मीट्रिक टन क्षमता का केंद्रीय वेयरहाउस

इकाई क्रमांक- 02 में चार बड़े गोदाम बनाए गए हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 20,000 मीट्रिक टन है। यहां राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त वनोपज का सुरक्षित भंडारण किया जाता है। वर्तमान में कोदो, कुटकी, रागी, हर्रा कचरिया, चिरायता, कालमेघ, पलास फूल और साल बीज सहित विभिन्न वनोपज का संग्रह किया गया है। इन उत्पादों का विक्रय संघ मुख्यालय रायपुर द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इन दोनों इकाइयों के संचालन से अब तक 5,200 से अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजित हो चुका है।

पीपीपी मॉडल पर हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट यूनिट की स्थापना

जामगांव एम में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना की गई है। यह यूनिट छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और स्फेयर बायोटेक कंपनी के संयुक्त प्रयास से बनी है, जिसका लोकार्पण वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और वन मंत्री श्री केदार कश्यप द्वारा किया गया था। लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में बनी इस यूनिट में गिलोय, कालमेघ, बहेड़ा, सफेद मुसली, जंगली हल्दी, गुड़मार, अश्वगंधा और शतावरी जैसे औषधीय पौधों से अर्क निकाला जा रहा है। इन अर्कों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं और वेलनेस उत्पादों के निर्माण में किया जाता है।

ग्रामीणों और संग्राहकों को स्थायी लाभ

हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट के माध्यम से ग्रामीण संग्राहकों से वनोपज और औषधीय पौधों का पूर्ण क्रय सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे उन्हें उचित मूल्य और नियमित आय मिल रही है। इससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और नए रोजगार अवसर भी सृजित हो रहे हैं। जामगांव एम की केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई, वेयरहाउस और हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट वनोपज की मूल्यवृद्धि के साथ-साथ ग्रामीणों और संग्राहकों के लिए आजीविका के मजबूत साधन बन रहे हैं।

नहीं, बल्कि मामले को ठंडा करने का माध्यम बन चुकी हैं।

इस दुखद घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी ने लोगों के घावों को और गहरा किया। जिस क्षेत्र में यह त्रासदी घटी, उसके प्रतिनिधि और राज्य के नगरीय विकास मंत्री, जिनके अधीन पेयजल आपूर्ति का विभाग आता है, उनकी असंवेदनशील टिप्पणियों ने जनता के आक्रोश को बढ़ाया। बाद में खेद प्रकट किया गया, लेकिन सवाल यह है कि खेद से क्या उन परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया? यह सही है कि उमा भारती जैसी वरिष्ठ नेत्री ने दोषियों से प्रायश्चित और दंड की मांग की, लेकिन देश का अनुभव बताता है कि ऐसी मांगें अक्सर समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं। मध्य प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार का खूब प्रचार किया जाता है, लेकिन इंदौर की घटना ने दिखा दिया कि यदि व्यवस्था की पटरियां जर्जर हों, तो इंजन कितने भी हों, दुर्घटना तय है।

नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधार, क्रियान्वयन और रूपांतरण की बात कही थी और जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रणालियों को अधिक अनुकूल बनाने पर जोर दिया था। लेकिन जब नागरिकों को स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, स्वस्थ चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं ही सुरक्षित रूप से उपलब्ध न हों, तो जीवनयापन को सुगम बनाने की बात खोखली लगती है। सर्वोच्च न्यायालय बार-बार स्पष्ट कर चुका है कि स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित जल का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इंदौर की यह त्रासदी इस अधिकार का खुला उल्लंघन है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर पानी में जहरीला पदार्थ मिलाए और उससे लोगों की मौत हो जाए, तो वह गंभीर अपराध माना जाता है। फिर जब प्रशासन की लापरवाही से जहरीला पानी घर-घर पहुंचता है और लोगों की जान जाती है, तो उसे अपराध क्यों नहीं माना जाए? यह गैर-इरादतन हत्या से कम गंभीर मामला नहीं है।

इंदौर की घटना यह भी उजागर करती है कि स्वच्छता रैंकिंग, स्मार्ट सिटी के दावे और चमकदार प्रचार व्यवस्थागत नाकामी को छिपा नहीं सकते। सड़कें साफ हो सकती हैं, दीवारें रंगी जा सकती हैं, लेकिन यदि पाइपलाइनों के भीतर जहर बह रहा है, तो ऐसा विकास जनता के साथ छल है। यह समस्या केवल इंदौर तक सीमित नहीं है। देश के अनेक छोटे-बड़े शहरों में जर्जर पाइपलाइनें, अवैज्ञानिक सीवर व्यवस्था और भ्रष्ट ठेकेदारी तंत्र वर्षों से नागरिकों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं हैजा फैलता है, कहीं पीलिया, कहीं दस्त और संक्रमण, लेकिन हर बार इसे स्थानीय समस्या कहकर टाल दिया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इंदौर की पंद्रह मौतें भी प्रशासन को जगाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं? क्यों नहीं ऐसी घटनाओं को आधार बनाकर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का बुलडोजर चलाया जाता? आज जब अवैध निर्माणों और गरीब बस्तियों पर बुलडोजर चल सकता है, तो प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं? क्यों उन अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं होते, जिनकी अनदेखी से लोगों की जान चली जाती है? क्यों सेवा से बर्खास्तगी और जेल की सजा जैसे कठोर कदम नहीं उठाए जाते?

यह घटना पूरे देश के लिए चेतावनी है। सभी राज्यों और स्थानीय निकायों को पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का गंभीरता से ऑडिट करना चाहिए। मुख्य पाइपलाइनों का नियमित निरीक्षण हो, सीवर और जल आपूर्ति लाइनों के बीच सुरक्षित दूरी सुनिश्चित की जाए और यह स्पष्ट तय हो कि किस स्तर का अधिकारी किस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार होगा। जवाबदेही केवल कागजों में नहीं, व्यवहार में दिखनी चाहिए। जब तक लापरवाही को अपराध नहीं माना जाएगा और दोषियों को वास्तविक दंड नहीं मिलेगा, तब तक ऐसी त्रासदियां दोहराती रहेंगी। आज भी देश में हर एक लाख आबादी पर औसतन लगभग 35 लोगों की दूषित पेयजल की वजह से जान जाती है। ग्लोबल एवरेज की तुलना में यह लगभग तीन गुना है। बेशक सरकार ने जल जीवन मिशन जैसे अभियान चलाए हैं, जिसकी बदौलत करीब 81 प्रतिशत ग्रामीण घरों में टैप वॉटर पहुंचाने का दावा है, लेकिन अब भी सुधार की बहुत जरूरत है। भारत ने 2047 तक विकसित देशों की कतार में खड़े होने का लक्ष्य रखा है, लेकिन पहले आम लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा। 2050 तक भारत की आबादी 1.7 अरब तक होने का अनुमान है और तब पानी के संसाधनों पर और दबाव पड़ेगा। देश को बेहतर वॉटर मैनेजमेंट के साथ सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, तभी इस चुनौती का सामना किया जा सकता है।

इंदौर की घटना केवल शोक व्यक्त करने का विषय नहीं है, यह व्यवस्था परिवर्तन की पुकार है। यदि इसे भी एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा कहकर भुला दिया गया, तो कल किसी और शहर में, किसी और गली में, कोई और परिवार इसी पीड़ा से गुजरेगा। जनता को अब नारों, पुरस्कारों और रैंकिंग से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे सवाल पूछने होंगे, जवाब मांगने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वच्छ भारत केवल झाड़ू और प्रचार से नहीं, बल्कि जवाबदेही, ईमानदारी और संवेदनशील प्रशासन से बने। यदि इंदौर की पंद्रह मौतें भी व्यवस्था की नींद नहीं तोड़ सकीं, तो यह मानना पड़ेगा कि गंदगी केवल पानी की पाइपलाइन में नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की नसों में बह रही है।

संभालना सीखता है। जून 2019 में जब अमित शाह केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने, तब जगत प्रकाश नड्डा को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। छह महीने बाद, जनवरी 2020 में नड्डा औपचारिक रूप से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब ठीक वही मॉडल नितिन नबीन पर लागू होता दिख रहा है।

बीजेपी संविधान के मुताबिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष दो कार्यकाल यानी कुल छह साल तक पद पर रह सकता है। नड्डा का कार्यकाल अब अपने अंतिम चरण में है। नितिन नबीन की नियुक्ति की टाइमिंग भी अपने आप में संदेश देती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, खरमास की अवधि में शुभ राजनीतिक फैसले टाल दिए जाते हैं। यही वजह है कि खरमास से ठीक पहले नबीन को वर्किंग प्रेसिडेंट घोषित किया गया। सूत्रों के अनुसार, 14 जनवरी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

बीजेपी देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 30 में संगठनात्मक चुनाव पूरा कर चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए यह आवश्यक शर्त होती है। पार्टी नेताओं के अनुसार, अध्यक्ष का चुनाव चार दिनों के भीतर पूरा हो सकता है। हालांकि चुनाव होगा, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की परंपरा आम सहमति से नाम तय करने की रही है। ऐसे में नबीन का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है।

युवा, पर अनुभवी- दो दशकों का संगठनात्मक सफर

नबीन की राजनीतिक यात्रा बिहार के युवा संगठन से शुरू हुई। एक समय जब भाजपा की जमीनी पकड़ केवल शहरी इलाकों और कुछ सीमित जिलों तक सीमित थी, नबीन ने उस समय से ही संगठनात्मक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। उनके पास लगभग दो दशकों का अनुभव है, जिसमें चुनावी जिम्मेदारियों का असीमित अनुभव शामिल है।

वे ऐसे नेता हैं जो जमीन पर उतरकर संगठन का काम समझते हैं। उनके कार्य का दायरा सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहा; संगठन की नीतियों को लागू करना, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन, और स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना ङ्क यह सब उनके नेतृत्व की विशेषता रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले छत्तीसगढ़ में उनके कार्यों को पहचाना और बाद में दिल्ली में भाजपा की अभियान टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। इसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी को राजधानी

तीन प्रमुख कारण जो नबीन की नियुक्ति के पक्ष में हैं

विश्लेषकों का कहना है कि नबीन के पक्ष में तीन प्रमुख कारण हैं, जो उनकी नियुक्ति को न केवल तर्कसंगत बनाते हैं बल्कि भाजपा के रणनीतिक निर्णय की गहराई को भी उजागर करते हैं।

1. **संगठन और जमीन स्तर की समझ-** नबीन ने हमेशा पार्टी के चुनावी और संगठनात्मक काम को समझने और उसे अंजाम देने पर ध्यान केंद्रित किया। बिहार से लेकर पूर्वी भारत तक उन्होंने पार्टी की जमीन पकड़ को मजबूत किया।
2. **नेतृत्व के साथ तालमेल-** नबीन वरिष्ठ नेतृत्व की शैली और उनकी कार्यप्रणाली को समझते हैं। वे सीमाओं के भीतर रहते हुए अपनी पूरी क्षमता से काम करने में विश्वास रखते हैं।
3. **कठिन कार्यों को पूरा करने की क्षमता-** नबीन ने कई जटिल चुनावी अभियान और संगठनात्मक चुनौतियों को सफलता पूर्वक पूरा किया है। चाहे वह छत्तीसगढ़ अभियान हो या दिल्ली की राजधानी में भाजपा की जीत का रोडमैप, नबीन ने हर बार अपनी रणनीतिक समझ और नेतृत्व कौशल का परिचय दिया।

नई पीढ़ी का प्रतीक

नबीन की नियुक्ति केवल संगठनात्मक मजबूती का संदेश नहीं देती; यह भाजपा की नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने की नीति का प्रतीक भी है। भाजपा लंबे समय से अपने नेतृत्व में युवा और अनुभवी संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है। हाल ही में गुजरात में हर्ष संघवी को उपमुख्यमंत्री बनाना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। कांग्रेस के 84 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व के विपरीत, भाजपा यह संदेश दे रही है कि पार्टी में युवा और मेहनती नेताओं को अवसर मिलेगा। नबीन की नियुक्ति इस दृष्टि से केवल पदोन्नति नहीं, बल्कि एक सशक्त रणनीतिक निर्णय है।

में लगभग तीन दशकों के चुनावी सूखे को तोड़ने में मदद मिली।

साधारण शब्दों में कहें, तो नबीन युवा हैं, पर उनका राजनीतिक अनुभव किसी वरिष्ठ नेता से कम नहीं। पाँच बार विधायक और महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके नबीन ने साबित किया है कि वे कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में भी सफलता हासिल कर सकते हैं।

सामुदायिक और क्षेत्रीय संतुलन

नबीन का सामाजिक और सामुदायिक आधार भी उनके पक्ष में जाता है। वे कायस्थ समुदाय से आते हैं, जो अक्सर राजनीतिक रूप से निष्पक्ष माना जाता है और अन्य समुदायों के साथ सीधे संघर्ष में नहीं देखा जाता। यह राजनीतिक संतुलन भाजपा के लिए लाभकारी है। बिहार में उनके संगठनात्मक कार्य और 'जीविका दीदी नेटवर्क' का सफल संचालन पार्टी के लिए मिसाल बन चुका है।

छत्तीसगढ़ अभियान में भी नबीन सक्रिय रहे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ मिलकर चुनावी जिम्मेदारी संभाली और चुनाव से डेढ़ साल पहले से ही राज्य में सक्रिय होकर पार्टी का मजबूत अभियान खड़ा किया। यह सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं थी, बल्कि यह संकेत भी था कि नबीन नेतृत्व में केवल पद नहीं, बल्कि परिणाम और सक्रियता भी महत्वपूर्ण है।

नेतृत्व की शैली और संगठनात्मक दृष्टिकोण

नबीन नेतृत्व के तरीके को समझते हैं और सीमा पार नहीं करते। वे वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का सम्मान करते हुए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं। उनकी यात्रा और कार्यशैली यह संकेत देती है कि वे संगठन की मजबूती और चुनावी तैयारी में पूरी ताकत झोंकेंगे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नबीन का यह तरीका भाजपा के लिए लाभकारी होगा। वे केवल चुनावी परिणामों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि संगठनात्मक ढांचे को भी मजबूत बनाएंगे। उनकी शैली में संयम, सक्रियता और रणनीति का अद्भुत मिश्रण है।

नितिन नबीन पर भाजपा का नवीन प्रयोग केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि संगठन, रणनीति और भविष्य की राजनीति का संकेत है। यह नियुक्ति पार्टी के लिए नया संदेश है- युवा नेतृत्व को मौका मिलेगा, संगठनात्मक क्षमता का सम्मान होगा और रणनीतिक सोच को महत्व दिया जाएगा।

भविष्य की संभावनाएँ

नबीन की नियुक्ति कई मायनों में भाजपा की राजनीतिक रणनीति को आकार देगी। पूर्वी भारत में पार्टी की पकड़ को मजबूत करने के साथ ही संगठन में नई ऊर्जा आएगी। यह कदम केवल पदोन्नति का प्रतीक नहीं, बल्कि यह संदेश है कि भाजपा में युवा नेतृत्व को स्थान मिलेगा, अनुभव का सम्मान रहेगा और रणनीति को प्राथमिकता दी जाएगी। इस नियुक्ति से पार्टी को चुनावी और संगठनात्मक लाभ होगा। नबीन की सक्रियता, रणनीतिक सोच और अनुभव का लाभ पार्टी की चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक मजबूती में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

नितिन नबीन पर भाजपा का नवीन प्रयोग केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि संगठन, रणनीति और भविष्य की राजनीति का संकेत है। यह नियुक्ति पार्टी के लिए नया संदेश है- युवा नेतृत्व को मौका मिलेगा, संगठनात्मक क्षमता का सम्मान होगा और रणनीतिक सोच को महत्व दिया जाएगा। 45 साल की उम्र में पांच बार विधायक और महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके नबीन ने यह साबित कर दिया है कि वे केवल पद के लिए नेता नहीं, बल्कि परिणाम, अनुभव और सक्रियता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। भाजपा के लिए नबीन की यह नियुक्ति एक नया यथार्थ है – युवा, अनुभवी और रणनीतिक नेतृत्व का संगम।

भविष्य में यह कदम भाजपा के संगठनात्मक और चुनावी समीकरणों को नया आकार देगा। नबीन की सक्रियता और रणनीतिक सोच के साथ, पार्टी केवल पदोन्नति का संदेश नहीं दे रही, बल्कि यह स्पष्ट कर रही है कि भारतीय राजनीति में नई पीढ़ी और संगठनात्मक अनुभव का संगम ही आने वाले समय की सच्ची शक्ति है।

इन्दौर की जल-त्रासदी और प्रशासनिक लापरवाही का नंगा चेहरा

यह घटना उस व्यवस्था का क्रूर और नंगा सच है, जो स्वच्छता के तमगों से सजी हुई है लेकिन भीतर से सड़ चुकी है। जिस शहर को लगातार सात वर्षों तक देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जाता रहा, वहीं दूषित पेयजल के कारण पंद्रह निर्दोष लोगों की मौत हो जाना पूरे तंत्र पर एक गहरा प्रश्नचिह्न है।

स्वच्छता रैंकिंग में लगातार टॉप पर आने वाले इंदौर में दूषित पेयजल की वजह से हुई मौतें कथनी और करनी की असमानता की पौल खोलती भयावह लापरवाही का नतीजा हैं। स्थानीय लोगों का यह आरोप बेहद गंभीर है कि पानी की क्वॉलिटी को लेकर लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई और दुर्भाग्य से इतनी बड़ी वारदात के बाद भी अदालत को दखल देकर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने का आदेश देना पड़ रहा है। यह केवल एक दुर्घटना नहीं है और न ही इसे तकनीकी खामी कहकर टाला जा सकता है। यह घटना उस व्यवस्था का क्रूर और नंगा सच है, जो स्वच्छता के तमगों से सजी हुई है लेकिन भीतर से सड़ चुकी है। जिस शहर को लगातार सात वर्षों तक देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जाता रहा, वहीं दूषित पेयजल के कारण पंद्रह निर्दोष लोगों की मौत हो जाना पूरे तंत्र पर एक गहरा प्रश्नचिह्न है। यह त्रासदी साबित करती है कि चमकदार रैंकिंग और पुरस्कार जीवन की वास्तविक सुरक्षा का विकल्प नहीं हो सकते। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन में सीवर का पानी मिल गया, जिससे हजारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया। सौ से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए, सैकड़ों बीमार पड़े और अनेक परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। सभ्य समाज में यह कल्पना ही आत्मग्लानि से भर देने वाली है कि जिस पानी को जीवनदायिनी मानकर पिया गया, वही सीवर की गंदगी से मिला हुआ था।

सबसे अधिक पीड़ादायक तथ्य यह है कि यह सब अचानक नहीं हुआ। नागरिकों ने पहले ही दूषित पानी की शिकायतें की थीं। पानी के रंग, गंध और स्वाद में बदलाव की जानकारी दी गई थी, लेकिन नगर निगम, जलप्रदाय विभाग और स्वास्थ्य तंत्र कुंभकर्णी नींद में सोए रहे। प्रशासन तब हरकत में आया जब मौतें हो चुकी थीं। यह लापरवाही नहीं, बल्कि गहरी संस्थागत असंवेदनशीलता, क्रूरता एवं अमानवीयता है। यह उस प्रशासनिक संस्कृति का परिणाम है जिसमें फाइलें और औपचारिकताएं मानव जीवन से अधिक मूल्यवान हो गई हैं। सवाल यह नहीं है कि पानी में सीवर कैसे मिला, असली सवाल यह है कि चेतावनियों के बावजूद इसे रोका क्यों नहीं गया? हर बार की तरह इस बार भी जांच समितियां बनीं, मुआवजे की घोषणाएं हुईं और कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। भले ही अपर नगर आयुक्त को इंदौर से हटा दिया है और प्रभारी अधीक्षण अभियंता से जिम्मेदारी वापस ले ली है। लेकिन, क्या इतना काफी है? इस तरह की 'रूटीन' कार्रवाई जिम्मेदारों को सबक नहीं देतीं, बल्कि पीड़ितों का मजाक बनाती हैं। क्या इन दिखावे की कार्रवाइयों से मृतकों का प्रायश्चित हो गया? क्या इससे भविष्य में ऐसी घटनाएं रुकेंगी? सच्चाई यह है कि जांच समितियां अब जवाबदेही तय करने का

बीता साल आर्थिक लिहाज़ से भारी उतार-चढ़ाव से भरा रहा।लंबी तेजी के बाद शेयर बाजार में सुस्ती आई, वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के दोबारा सत्ता में आने के साथ टैरिफ को लेकर सख्त रुख अपनाया गया। इन चुनौतियों के बीच भारत ने संतुलन और दृढ़ता का परिचय दिया।

भारत की आर्थिक कहानी और वैश्विक भविष्य की तस्वीर

साल 2025 से 2026 में कदम रखना केवल कैलेंडर का पन्ना पलटना भर नहीं है, बल्कि यह आत्ममूल्यांकन और नव-आरंभ का अवसर है। वास्तव में सच तो यह है कि यह समय उन सपनों और लक्ष्यों को फिर से साधने का है, जो बीते वर्ष परिस्थितियों, सीमाओं या संकोच के कारण अधूरे रह गए। साथ ही, यह आने वाली चुनौतियों को पहचानकर उनके लिए स्वयं को मानसिक, बौद्धिक और व्यवहारिक रूप से तैयार करने की प्रेरणा देता है। नया वर्ष हमें अतीत से सीख लेकर भविष्य की ओर आशा, संकल्प और सकारात्मक दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। कोई भी साल पूरी तरह आदर्श नहीं होता, और 2025 भी इसका अपवाद नहीं रहा। हालांकि, उससे मिली सीख नए वर्ष में दिशा दिखा सकती है। बीता साल आर्थिक लिहाज़ से भारी उतार-चढ़ाव से भरा रहा।लंबी तेजी के बाद शेयर बाजार में सुस्ती आई, वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के दोबारा सत्ता में आने के साथ टैरिफ को लेकर सख्त रुख अपनाया गया। इन चुनौतियों के बीच भारत ने संतुलन और दृढ़ता का परिचय दिया। ट्रंप के दबाव के बावजूद रूस के साथ संबंधों को प्राथमिकता देकर भारत ने स्पष्ट किया कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है। इसी अवधि में रूस, न्यूज़ीलैंड और ओमान के साथ महत्वपूर्ण समझौते भी हुए, जो भारत की कूटनीतिक सक्रियता और आत्मनिर्भर सोच को दर्शाते हैं।

जैसा कि पाठक जानते होंगे कि पिछले साल देश के भीतर जीएसटी 2.0 जैसे बड़े सुधार लागू किए गए, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अच्छी खासी मजबूती मिली। इसका असर यह रहा कि दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि 8.2त्न रही।साल के अंत तक भारत के जापान को पीछे छोड़कर लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान उसकी तेज़ और निरंतर आर्थिक वृद्धि पर आधारित है। कहना ग़लत नहीं होगा कि मजबूत घरेलू मांग, बढ़ता मध्यम वर्ग, सरकारी पूंजीगत खर्च, बुनियादी ढांचे में निवेश और जीएसटी जैसे संरचनात्मक सुधारों ने आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। साथ ही, वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव और भारत को वैकल्पिक उत्पादन केंद्र के रूप में मिल रहा भरोसा निवेश और निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। इसके विपरीत, जापान की अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि, घटती आबादी और सीमित घरेलू मांग से जूझ रही है। इन सभी कारणों के चलते भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है और मौजूदा अनुमानों के अनुसार वह वर्ष के अंत तक जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच सकता है।इसके अलावा, अन्य देशों के साथ हुई व्यापार संधियाँ और अमेरिका के साथ होने वाला समझौता पूरा होने से आगे चलकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। दूसरे शब्दों में कहें तो वैश्विक स्तर पर आर्थिक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत बने रहने की संभावना है। इसका मुख्य कारण देश के भीतर मजबूत मांग, महंगाई का नियंत्रण में रहना और सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की संतुलित आर्थिक नीतियां हैं।

अर्थव्यवस्था के मामले में 2030 तक जर्मनी को पछाड़ देगा भारत

अनुमान है कि भारत 2030 तक जर्मनी को भी पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। सरकार ने भरोसा जताया है कि मजबूत आर्थिक नींव के साथ, भारत की जीडीपी 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी।आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, देश के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अच्छी स्थिति में हैं, उनके पास पर्याप्त पूंजी और नकदी भंडार है, खराब कर्ज में कमी आई है और उनका मुनाफा भी मजबूत बना हुआ है।

पोषण निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं सूरजपुर की महिलाएं

आर्थिक सशक्तिकरण की नींव सशक्त मानसिकता पर आधारित होती है। दृढ़ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास व्यक्ति को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। सूरजपुर जिले की स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने इस सोच को व्यवहार में उतारते हुए आत्मनिर्भरता की एक सशक्त मिसाल प्रस्तुत की है। ये महिलाएं न केवल स्वयं सशक्त बन रही हैं, बल्कि जिले की महिलाओं एवं बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने के अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तत्काल उपभोग हेतु तैयार पोषण आहार (रेडी टू ईट) निर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। इन संयंत्रों में स्वादिष्ट एवं पौष्टिक नमकीन दलिया तथा मीठा शक्ति आहार का निर्माण किया जा रहा है, जो विटामिन 'ए', विटामिन 'डी', थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइरीडॉक्सिन, फोलिक अम्ल, कोबालामिन, लोह तत्व (आयरन), कैल्शियम एवं जिंक जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर है।

जिले प्रशासन द्वारा जिले में कुल 07 पोषण आहार निर्माण संयंत्र स्थापित किए गए है। यहां वर्तमान में भैयाथान, प्रतापपुर एवं सूरजपुर विकासखंड में तीन संयंत्रों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इन तीनों संयंत्रों में 32 महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से पोषण आहार निर्माण कार्य में संलग्न हैं। निर्मित पोषण आहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को नि:शुल्क प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार स्व-सहायता समूहों की महिलाएं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण में अप्रत्यक्ष किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात है कि पोषण आहार के निर्माण के साथ-साथ उसके वितरण की भी जिम्मेदारी भी महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपी गई है।

भैयाथान विकासखंड में 15 स्व-सहायता समूह,सूरजपुर विकासखंड में 15 स्व-सहायता समूह तथा प्रतापपुर विकासखंड में 13 स्व-सहायता समूह सक्रिय रूप से वितरण कार्य में अपनी भूमिका निभा रही है।

इन समूहों के माध्यम से कुल 430 महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों तक पोषण आहार वितरण कार्य में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं।

इस योजना से महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। मानसिक रूप से सशक्त ये महिलाएं अब घरेलू कार्यों के साथ-साथ आजीविका से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। यह पहल न केवल निश्चित रूप से जिले में पोषण स्तर सुधारने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत कर रही है।

कांगेर घाटी में मिली अनोखी 'ग्रीन गुफा'

छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जैव विविधता और विश्व-प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के लिए देश-विदेश में विख्यात है। इसी कड़ी में अब कांगेर घाटी में एक और अनोखी प्राकृतिक स्थलाकृति सामने आई है, जिसे 'ग्रीन केव' (ग्रीन गुफा) नाम दिया गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा पर्यटन और वन्य धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रीन गुफा के पर्यटन मानचित्र में शामिल होने से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय विकास को गति प्राप्त होगी और शीघ्र ही पर्यटक इस अद्भुत गुफा की प्राकृतिक खूबसूरती का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे। वन विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां पूर्ण किए जाने के बाद शीघ्र ही इस गुफा को पर्यटकों के लिए खोले जाने की योजना है।

उल्लेखनीय है कि यह ग्रीन गुफा कोटुमसर परिसर के कंपार्टमेंट क्रमांक 85 में स्थित है। गुफा की दीवारों और छत से लटकती चूने की आकृतियों (स्टैलेक्टाइट्स) पर हरे रंग की सूक्ष्मजीवी परतें पाई जाती हैं, जिसके कारण इसे 'ग्रीन केव' नाम दिया गया है। चूना पत्थर और शैल से निर्मित यह गुफा कांगेर घाटी की दुर्लभ और विशिष्ट गुफाओं में से एक मानी जा रही है।

ग्रीन गुफा तक पहुंचने का मार्ग बड़े-बड़े पत्थरों से होकर गुजरता है। गुफा में प्रवेश करते ही सूक्ष्मजीवी जमाव से ढकी हरी दीवारें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। आगे बढ़ने पर एक विशाल कक्ष दिखाई देता है, जहां से भीतर की ओर चमकदार और विशाल स्टैलेक्टाइट्स तथा फ्लो-स्टोन (बहते पानी से बनी पत्थर की परतें) देखने को मिलती हैं, जो गुफा की प्राकृतिक भव्यता को और भी बढ़ा देती हैं।

> **"घने जंगलों के मध्य स्थित यह गुफा अपनी अनोखी संरचना और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र बनने जा रही है। वन विभाग द्वारा गुफा की सुरक्षा एवं नियमित निगरानी की जा रही है।"**

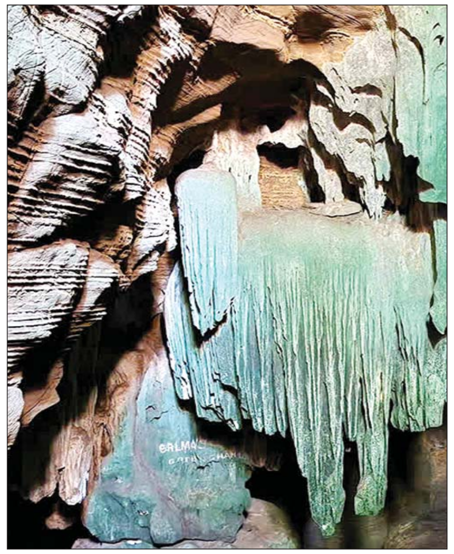

घने जंगलों के मध्य स्थित यह गुफा अपनी अनोखी संरचना और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र बनने जा रही है। वन विभाग द्वारा गुफा की सुरक्षा एवं नियमित निगरानी की जा रही है। साथ ही पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहुंच मार्ग, पैदल पथ तथा अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास कार्य प्रगति पर है। वन विभाग द्वारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

लोगों की उम्मीदें तत्परता से हो रही पूरी

जनदर्शन में तत्काल सुलझी समस्याएं

लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच का सीधा संवाद ही सुशासन की असली कसौटी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 'जनदर्शन' के माध्यम से अंतिम छोर के व्यक्ति की पीड़ा सुन रहे हैं और मौके पर ही उनका समाधान भी कर रहे हैं। इससे न केवल लोगों की उम्मीदें तत्परता से पूरी हो रही हैं, बल्कि यह नागरिकों में व्यवस्था के प्रति विश्वास भी बढ़ा रहा है। लोगों की जरूरतों, मांगों और तकलीफों के प्रति संवेदनशीलता के साथ तत्परता साबित करती है कि संवेदनशीलता ही सुशासन के केंद्र में है। जब लोगों की उम्मीदों और जन आकांक्षाओं को मुख्यमंत्री की सहृदयता से पंख मिलते हैं, तो सही मायनों में अंत्योदय का सपना साकार होता है। आज के जनदर्शन में कुल 1950 आवेदन प्राप्त हुए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के राजधानी रायपुर स्थित शासकीय निवास कार्यालय में आज आयोजित जनदर्शन सेवा, संवेदना और समाधान का त्रिवेणी संगम बन गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने एक बार फिर साबित किया कि जन सरोकारों से जुड़ी समस्याओं का निराकरण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घंटों तक प्रदेश के कोने-कोने से आए फरियादियों की अर्जी सुनी। लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने तत्काल ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। कई जरूरतमंदों के लिए तुरंत आर्थिक सहायता मंजूर की।

दिव्यांगों के जीवन से छटेगा अंधेरा, अब खुद तय करेंगे अपनी राह

मुख्यमंत्री श्री साय ने आज के जनदर्शन ने कई दिव्यांगजनों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। रायपुर के खामतराई के श्री जीवन दास मानिकपुरी और आरंग के श्री भारत साहू को मुख्यमंत्री ने जब बैटरीचलित ट्राइसिकल सौंपी, तो उनकी आंखों में आत्मनिर्भरता की चमक साफ दिखाई दी। अब उन्हें कहीं आने-जाने के लिए किसी और का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। इसी तरह रायपुर के चंदू यादव और सुमन साहू को भी ट्राइसिकल व व्हीलचेयर प्रदान की गई। वहीं, सुनने की क्षमता खो चुके सागर नायक और उमेश पटेल को तत्काल श्रवण यंत्र उपलब्ध कराए गए, जिससे वे अब दुनिया की आवाजें सुन सकेंगे।

> **संवेदनशीलता ही सुशासन का आधार- मुख्यमंत्री साय**
>
> मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जनदर्शन में कहा कि यह केवल आवेदन लेने का माध्यम नहीं, बल्कि आम जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही का प्रतीक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनदर्शन में आने वाले हर आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि जरूरतमंदों को भटकना न पड़े।

जनदर्शन में महासमुंद जिले के ग्राम बड़ेटेमरी की श्रीमती बसंती साव की बड़ी उम्मीद आज पूरी हुई। पैरों से लकवाग्रस्त बसंती ने जब इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत और अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री को दी, तो श्री साय ने तनिक भी देरी नहीं की। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल निर्देशित कर मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना से पांच लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई। बसंती को इससे पहले भी शासन से 75 हजार रुपए की मदद मिल चुकी है। मुख्यमंत्री की इस त्वरित कार्रवाई ने बसंती के परिवार को बड़ी चिंता से मुक्त कर दिया। श्री साय ने इलाज के साथ ही शिक्षा व अन्य जरूरतों के लिए भी कई लोगों के लिए आर्थिक सहायता की तत्काल मंजूरी दी।

जनदर्शन में रायपुर के तात्यापारा निवासी 60 वर्षीय अविवाहित श्रमिक श्री हनुमंत राव की समस्या का भी त्वरित निराकरण हुआ। माता-पिता के निधन के बाद राशन कार्ड की पात्रता को लेकर जूझ रहे श्री राव ने अपनी व्यथा मुख्यमंत्री को सुनाई। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड न होने से वे सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। मुख्यमंत्री ने आत्मीयता से उनकी बात सुनी और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को तत्काल उनका राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सूरज नगर लाभांडी, रायपुर निवासी दिव्यांग 17 वर्षीय राज शर्मा की भी समस्या का त्वरित निदान किया। उन्होंने दोनों पैरों से दिव्यांग राज को 20 हजार रुपए का चेक देकर तात्कालिक सहायता प्रदान की। श्री साय ने श्री फूल गिरी गोस्वामी को बेटी की शादी के लिए 20 हजार रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया।

रायगढ़ निवासी दोनों पैरों से दिव्यांग ओमप्रकाश निषाद को भी उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने तत्काल 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की।